लखनऊ

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025
वर्ष : 11 । अंक: 29
मूल्य : 1 रुपये
पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

"जीवन में जो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है,और दूसरों को भी सहायता करता है वही अच्छा इन्सान कहलाता है।"

TODAY WEATHER

DAY 37° Hi | NIGHT 26° Low

संक्षेप

भारत चौतरफा घिरा, विदेश नीति विफल, अमेरिकी टैरिफ के बाद अखिलेश यादव का हमला

नई दिल्ली। भारत पर 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ की घोषणा के बाद राजनीतिक घमासान मचा है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की विदेश नीति पूरी तरह विफल हो रही है। कहीं ना कहीं हमारा भारत संकट में है और देश चौतरफा घिरा है। दिल्ली में अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, सरकार विदेश नीति पर पूरी तरह विफल रही है। किसान के हितों के लिए वादा किया था, लेकिन किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाई है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है। जिस तरह पाबंदियां लग रही हैं, कहीं ना कहीं हमारा देश और अर्थव्यवस्था संकट में है। किसान और नौजवान भी संकट में है। भारत चौतरफा घिर गया है। अमेरिकी टैरिफ के दबाव में भारत ने झुकने से इनकार कर दिया है? इस सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका से रिश्ते भारत को रखने ही पड़ेंगे। उन्होंने कहा, अमेरिका के साथ रिश्ते आज के नहीं हैं, यह बहुत पहले से रहे हैं। उन रिश्तों को मजबूत कैसे किया जाए, इस दिशा में काम होना चाहिए। कारोबारी और किसानों के हितों में सोचना चाहिए। सपा प्रमुख ने सवाल उठाते हुए आगे कहा, सोचने की बात है कि आज सरकार को यह क्यों कहना पड़ रहा है? यह दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे पर भी अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी जरूर लेकर जाएं, क्योंकि वह नाम बदलने में आगे हैं और हो सकता है वह चीन का भी नाम बदल दें।

ट्रंप के टैरिफ पर भड़के शशि थरूर, कहा- अगर तीन हफ़्तों में बदलाव नहीं आता है तो...

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और पूर्व वैश्विक राजनयिक शशि थरूर ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से भारत की खरीद पर दंड के तौर पर उस पर भारी टैरिफ लगाया है, लेकिन चीन को अधिक छूट दी है, जिसमें एक छिपा हुआ संदेश प्रतीत होता है। उन्होंने भारत द्वारा रूस से खरीदे जा रहे तेल के बारे में कहा कि चीन लगभग दोगुना तेल खरीद रहा है और अतिरिक्त टैरिफ लागू होने से पहले उन्हें 90 दिन का समय दिया गया है, जबकि भारत को केवल तीन सप्ताह का समय दिया गया है। पहले से घोषित 25% टैरिफ गुरुवार को लागू हो गया; इस महीने के अंत में इसे 50% तक बढ़ाया जाना है। संसद के बाहर पत्रकारों से हिंदी में बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'अगर अगले तीन हफ़्तों में कोई बदलाव नहीं आता है, तो हमें वही दरें लागू करनी चाहिए।' उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सिर्फ़ 'पारस्परिक' शब्द का इस्तेमाल किया है। भारत की कोई धमकी देने की नीति नहीं है, इसलिए हमें तीन हफ़्ते इंतज़ार करना चाहिए और अगर कोई बदलाव नहीं आता है, तो जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अमेरिकी आयातों पर भारत का टैरिफ़ या शुल्क औसतन 17% है, इसलिए ट्रंप द्वारा लगाई गई दरें सिर्फ़ पारस्परिक नहीं लगतीं। उन्होंने कहा कि लगता है वाशिंगटन से कोई और छिपा हुआ संदेश आया है। सरकार को स्थिति को ध्यान से समझने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए।

किसानों के हितों के लिए मैं कीमत चुकाने को तैयार...

टैरिफ संकट के बीच पीएम मोदी का बयान

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका टैरिफ संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों और मछुआरों के हित को ध्यान में रखकर एक बड़ा बयान दिया है। पीएम ने कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई-बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मोदी ने यह भाषण दिल्ली के आईसीएआर पूसा में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया।

बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर तनाव चल रहा है। दरअसल इस तनाव का एक कारण भारत और अमेरिका बीच प्रस्तावित डील का न हो पाना है। माना जाता है कि दोनों देशों के बीच कृषि और डेयरी को लेकर सहमति नहीं बन पाई। भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्रों में रियायतों को लेकर अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दी थीं। भारत ने कृषि और डेयरी उत्पादों पर शुल्क रियायतें देने से इनकार कर दिया थी, क्योंकि ये दोनों विषय संवेदनशील हैं। भारत ने कभी भी किसी व्यापार समझौते में डेयरी क्षेत्र को नहीं खोला है।

इसके साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। अमेरिका भारत के साथ डेयरी व्यापार समझौता करना चाहता है लेकिन भारत का कहना है कि वह अपने देश में ऐसे दूध या डेयरी उत्पाद की अनुमति नहीं दे सकता, जो उन गायों से प्राप्त होता हो जिन्हें मांसाहारी चीजे खिलाई जाती हैं।

किसानों की प्रगति के लिए लगातार कर रहें हैं काम

पीएम ने कहा कि मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशु पालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाने के लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है।

पीएम धन धान्य योजना को मिली मंजूरी

मोदी ने बताया कि हाल ही में पीएम धन धान्य योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत उन 100 जिलों को चुना गया है, जहां खेती पिछड़ी रही। यहां सुविधाएं पहुंचाकर, किसानों को आर्थिक मदद देकर, खेती में नया भरोसा पैदा किया जा रहा है। 10 हजार FPOs के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेटिव और सेल्फ हेल्फ ग्रुप को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। इसके साथ ही e-NAM की वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी हुई है।

किसानों का भरोसा बढ़ाने का किया प्रयास

मोदी ने कहा कि बीते सालों में जो नीतियां बनी, उनके द्वारा हमने सिर्फ मदद नहीं की थी बल्कि किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी किया था। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से दूर किया गया है।

शिक्षकों को अब ट्रांसफर से जुड़ी परेशानी का नहीं करना पड़ेगा सामना, सीएम ने किया बड़ा ऐलान

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन से पहले शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। शिक्षकों के ट्रांसफर संबंधित इस ऐलान से उन शिक्षकों को राहत मिलेगी जो अपने जिले से दूर दूसरे जिले में छात्रों को पढ़ाने जाते हैं। सीएम नीतीश कुमार को शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित कई सुझाव मिले हैं, जिसके तहत अब अंतर जिला ट्रांसफर से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों को ट्रांसफर से संबंधित समस्याएं हैं, उनसे तीन जिलों का विकल्प लिया जाए और उनकी पोस्टिंग उन्हीं जिलों में की जाए। यह निर्णय शिक्षकों की सुविधा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उठाया गया कदम है। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, शिक्षा विभाग द्वारा हाल में किए गए शिक्षकों के स्थानान्तरण के बारे में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निदेश दिया है कि अन्तर जिला स्थानान्तरण संबंधी जिन शिक्षकों की भी समस्या है।

'दिव्यांगजनों के लिए भी फुटपाथ जरूरी', अदालत ने केंद्र सरकार को गाइडलाइन बनाने का आदेश दिया

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के सभी नागरिकों, विशेषकर दिव्यांगों और बुजुर्गों को सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह चार हफ्तों के भीतर ऐसे दिशा-निर्देश बनाए, जो देशभर में सभी फुटपाथों को सुलभ और अतिक्रमणमुक्त बनाएं। यह आदेश डॉक्टर एस. राजासेकरन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें उन्होंने भारत के फुटपाथों की दयनीय स्थिति और दिव्यांगजनों की परेशानियों को उजागर किया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि देश में कई जगह फुटपाथ हैं ही नहीं, और जहां हैं वहां या तो टूटे-फूटे हैं या अतिक्रमण के शिकार हैं। इससे न सिर्फ दिव्यांगों की आवाजाही मुश्किल होती है बल्कि आम पैदल यात्रियों की जान भी खतरे में रहती है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हवाला देते हुए दलील दी गई कि हर नागरिक को समानता और जीवन का अधिकार है, जिसमें सुरक्षित चलना भी शामिल है।

अगली सुनवाई एक सितंबर को, जवाबदेही तय होगी

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करे। अगली सुनवाई एक सितंबर 2025 को होगी, जिसमें केंद्र और राज्यों की जवाबदेही की समीक्षा की जाएगी। कोर्ट के इस आदेश ने दिव्यांगों और पैदल यात्रियों के अधिकारों को मजबूती से सामने रखा है।

तीन अहम मुद्दों पर गाइडलाइन बनाने को कहा

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि अभी तक इस विषय पर कोई ठोस राष्ट्रीय दिशा-निर्देश नहीं हैं। इसलिए केंद्र सरकार को तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियम बनाने होंगे। पहला, सभी नई और पुरानी सड़कों पर तकनीकी मानकों के साथ फुटपाथ की अनिवार्यता तय करना। दूसरा, डिजाइन ऐसा हो कि दिव्यांगजनों को कहीं भी दिक्कत न हो। तीसरा, अतिक्रमण को हटाने और रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना।

अगर केंद्र फेल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट बनाएगा नियम

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर केंद्र सरकार तय समय में गाइडलाइन नहीं बनाती है, तो अदालत खुद अमिकस क्यूरी (अदालत के मित्र) की मदद से दिशानिर्देश तैयार करेगी। इसके साथ ही राज्यों को छूट दी गई है कि वे या तो इन राष्ट्रीय गाइडलाइनों को अपनाएं या अपनी गाइडलाइंस बनाएं, लेकिन मानक एक जैसे होने चाहिए।

हमारी नागरिकता छीनना चाहती है डबल इंजन सरकार : ममता

झाड़ग्राम (पश्चिम बंगाल)। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की मांग कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि डंबल इंजन सरकार राज्य के लोगों की नागरिकता छीनना चाहती है। झाड़ग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, 'मैं सोच रही हूं, क्या हम वाकई आजाद हैं? मुझे डर है कि कहीं हमारी नागरिकता छीन न ली जाए। कृपया हमें वंचित न करें।'

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार नागरिकों को गलत तरीके से रोहिंग्या बताकर हिरासत केंद्रों में डाल रही है और फिर उन्हें बांग्लादेश भेजने की साजिश कर रही है। उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि वह जनकल्याण के मुद्दों पर फोकस करने के बजाय हर बात को लेकर कोर्ट भागती है।

ममता बनर्जी ने कहा, डबल इंजन सरकार हमारी नागरिकता छीनना चाहती है। हमें रोहिंग्या बताकर हिरासत केंद्रों में डालना चाहती है और फिर बांग्लादेश भेजना चाहती है। भाजपा हर बात पर कोर्ट जाती है। मेरे पास 1912 का दस रुपये का नोट है जिस पर बंगाली में लिखा है, फिर भी वे कहते हैं कि बंगाली भाषा नहीं है। इससे पहले भाजपा सांसद और पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा था कि अगर मुख्यमंत्री यह सोचती हैं कि वह अवैध मतदाताओं की मदद से फिर से सत्ता में आएंगी, तो यह उनकी गलतफहमी है। सामिक भट्टाचार्य ने कहा, उन्हें विरोध करने दीजिए। ममता बनर्जी की मांग है कि मृत लोगों के नाम सूची से न हटाए जाएं। अगर उन्हें लगता है कि वे बांग्लादेशियों, जिहादियों, रोहिंग्याओं, अवैध प्रवासियों और अवैध मतदाताओं की मदद से चौथी बार सत्ता में आएंगी, तो यह उनकी भूल है।

जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया है। दरअसल, जस्टिस वर्मा ने अपने आवास से जला हुआ कैश मिलने के मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट को अमान्य करार देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाने के लिए भेजी गई सिफारिश को भी चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने स्पष्ट किया कि अदालत ने यह माना है कि इस पूरी प्रक्रिया से याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ।

यूपी में तीन घंटे में तीन बड़े एनकाउंटर, पत्रकार हत्याकांड के दो शूटर और झारखंड का कुख्यात अपराधी ढेर

आर्यावर्त क्रांति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को मात्र तीन घंटे के भीतर तीन एनकाउंटर में तीन कुख्यात अपराधियों को ढेर कर दिया। इनमें एक झारखंड का कुख्यात अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह शामिल है, जबकि सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में वांछित दो शूटर भी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए।

पहली मुठभेड़ प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में हुई। झारखंड के धनबाद निवासी कुख्यात अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह की मौजूदगी की सूचना मिलने पर एसटीएफ प्रयागराज की टीम ने शिवराजपुर चौराहे के पास घेराबंदी की। एसटीएफ के ललकारने पर छोटू सिंह ने एके-47 और 9 एमएम पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह गोली लगने से घायल हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल से एक एके-47, 9 एमएम पिस्तौल, भारी मात्रा में कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। मुठभेड़ में एसटीएफ के तीन जवान बाल-बाल बचे।

दूसरी बड़ी कार्रवाई सीतापुर जिले के पिसावां थाना क्षेत्र में हुई। हरदोई-सीतापुर सीमा पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या में शामिल दोनों शूटरों को ढेर कर दिया गया।

गौरतलब है कि आठ मार्च को हेमपुर ओवरब्रिज पर पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पहले ही दो आरोपियों—कारदेव मंदिर के बाबा सहित—को जेल भेजा जा चुका है, जबकि दोनों शूटर फरार चल रहे थे। इन पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस की टीमें लगातार उनकी तलाश में जुटी थीं।

'वोटर लिस्ट में मकान संख्या 0 और पिता का नाम hhgassjk मिला', राहुल गांधी ने जारी किए 'धांधली के सबूत'

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोटर लिस्ट में धांधली से जुड़े अपने आरोपों के सबूत जारी किए। उन्होंने कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी की गई। इसके अलावा राहुल ने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के नतीजों पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कर्नाटक लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट और वोटिंग में धांधली को लेकर बात की। कांग्रेस सांसद ने कहा, एग्जिट पोल कुछ और कहते हैं, लेकिन जब नतीजे आते है तो चीजें बदल जाती है। इसी के साथ राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हमला किया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में 40 लाख रहस्यमयी वोटर है।

राहुल गांधी ने कहा, एक समय था जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं थी, पूरा देश एक दिन वोट करता था। लेकिन आज के जमाने में यूपी में अलग-अलग वोटिंग होती है। बिहार में कभी और हो रही है। महीनों के लिए वोटिंग चलती है। हम इसी को लेकर चिंतित है। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र में 5 महीने में इतने वोटर जुड़े हैं जितने 5 साल में नहीं जुड़े। महाराष्ट्र की पूरी जनसंख्या से ज्यादा वोटर जुड़े हैं। जिससे और ज्यादा संदेह पैदा होता है। राहुल गांधी ने आगे कहा, चुनाव आयोग ने हमें वोटर लिस्ट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को मशीन के पढ़ने योग्य (मशीन रीडेबल) डेटा उपलब्ध नहीं करा रहा है ताकि ये सब पकड़ा ना जा सके। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में कहा कि 5:30 बजे के बाद भारी मात्रा में वोटिंग हुई है। लेकिन, हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है।

चुनाव आयोग ने मांगा लिखित प्रमाण

कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को लिखे पत्र में कहा है कि निर्वाचन नियमों के तहत, अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची की वैधता पर सवाल उठाता है, तो उसे लिखित में विवरण देना होता है। पत्र में राहुल से अपेक्षा की गई है कि वे नियम 20(3)(b) के तहत शपथपत्र पर हस्ताक्षर कर ऐसे मतदाताओं के नाम उपलब्ध कराएं, ताकि उनके दावों की जांच की जा सके और यदि आवश्यक हो तो कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सके।

कैसे वोट चोरी का लगाया पता

राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह से वोट चोरी का उन्होंने पता लगाया। उन्होंने एक लिस्ट दिखाई और बताया कि ऐसी लिस्ट होती है और एक व्यक्ति की फोटो को लेकर हम हर शीट में चेक करते हैं कि यह व्यक्ति का नाम दो बार तो नहीं आया है।

'उनके सारे झूठ उजागर हो रहे हैं', PM मोदी के व्यक्तिगत कीमत चुकाने वाले बयान पर उद्धव का वार

मुंबई, एजेंसी। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर किसानों को लेकर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दो से तीन साल तक जो किसान दिल्ली आना चाहते थे, उन्हें रोका गया। कुछ गरीब किसान मर गए। तब सरकार को उनकी याद नहीं आई। अब जब चुनाव नजदीक हैं, तो किसान फिर से याद आने लगे हैं।

उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि जब उनके पिता बालासाहेब ठाकरे भूख हड़ताल पर थे, तो उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया गया। उन पर बंदूकें चलाई गईं, दीवारें खड़ी की गईं और उन्हें नक्सली कहा गया। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन अब धीरे-धीरे केंद्र के सारे झूठ उजागर हो रहे हैं, और उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। वहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे भी दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, तो उद्धव ठाकरे ने दो टूक कहा, "दोनों भाई काफी सक्षम हैं। हमें जो करना होगा, हम करेंगे। किसी तीसरे व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत कभी भी अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं करेगा, भले ही इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से भारी कीमत चुकानी पड़े। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क 50% तक बढ़ा दिया है और दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर तनातनी चल रही है।

पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड के दो शूटरों का एनकाउंटर, पिसावां में मुठभेड़ में ढेर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सीतापुर। सीतापुर के महोली निवासी पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दो शूटरों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में मारे गए शूटरों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम था।

जानकारी के अनुसार, सीतापुर के महोली निवासी पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में वांछित और एक-एक लाख रुपये के इनामिया बदमाश संजय तिवारी और राजू तिवारी की बृहस्पतिवार सुबह पिसावां में पुलिस से मुठभेड़ हुई।

पुलिस से मुठभेड़ में दोनों शूटर घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। शूटरों के

मारे जाने के बाद राघवेंद्र के परिवार से भी प्रतिक्रिया आई है। राघवेंद्र की पत्नी इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं।

एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि पिसावां महोली मार्ग पर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम काम्बिंग कर रही थी। इसी दौरान शूटर संजय तिवारी और राजू तिवारी बाइक से जा रहे थे। पुलिज ने बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया तो दोनों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया।

मुठभेड़ में शूटरों को लगी गोली

पुलिस ने भी क्रॉस फायरिंग की। दोनों शूटरों को मुठभेड़ में गोली लग गई। उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि दोनों वांछित थे। शूटरों की पहचान संजय तिवारी उर्फ अकील खान और राजू तिवारी उर्फ रिजवान के रूप में हुई है। दोनों मिश्रित के अटवा निवासी हैं। इन पर हत्या का प्रयास, हत्या और अन्य कई गंभीर मामले दर्ज थे।

आठ मार्च को हुई थी राघवेंद्र की हत्या

बता दें कि इसी वर्ष आठ मार्च को राघवेंद्र की हेमपुर ओवरब्रिज पर करीब दोपहर तीन बजे दो शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने 34 दिनों के बाद हत्याकांड का खुलासा कर एक पुजारी और दो अन्य को जेल भेजा था। इस मामले में दोनों शूटर फरार चल रहे थे। इनकी तलाश में टीमें लगी थीं।

राघवेंद्र हत्याकांड में शामिल थे पांच लोग

आठ मार्च को हुए पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड का 34 दिन बाद पुलिस ने खुलासा किया था। हत्याकांड में पांच लोग शामिल थे जिनमें से तीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। साजिश में शामिल कारेदेव बाबा मंदिर के पुजारी को उनके दो परिचितों संग गिरफ्तार किया गया था। वहीं, गोली मारने वाले दो शूटरों को वांछित घोषित किया गया था। उन्हें पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की तीन टीमों के अलावा एसटीएफ की सात टीमें लगी थीं।

राघवेंद्र बाजपेयी की पत्नी रश्मि बोलीं- हम संतुष्ट नहीं हैं

शूटरों की पुलिस से मुठभेड़ की जानकारी अमर उजाला ने राघवेंद्र बाजपेयी की पत्नी रश्मि बाजपेयी को दी। रश्मि बाजपेयी ने कहा कि पति के अंतिम संस्कार से पहले हमने कहा था कि घटना का खुलासा हमारी जानकारी में होना चाहिए। अगर शूटर पकड़े जाएं तो हमें दिखाया जाए। न तो खुलासा हमें बताकर हुआ और न एनकाउंटर से पहले दोनों के बारे में जानकारी दी गई। हम इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं।

गांव का सूखा कुआं दे रहा है बड़ी दुर्घटना का संकेत

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुलतानपुर। जिले के दूबेपुर ब्लॉक स्थित पलहीपुर भटपुरवा ग्रामसभा में सोमवार शाम लगभग 5 बजे एक बड़ा हादसा टल गया। 11 वर्षीय बालक अर्क शर्मा, पुत्र पवन शर्मा पत्रकार, रस्ते से जाते समय गांव के पुराने और सूखे पड़े लगभग 36 फिट गहरे कुएं में साइकिल के साथ गिर पड़ा। गांववासियों की सतर्कता और सूझबूझ से बालक को तुरंत बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। साइकिल की स्थित को देख कर बालक का बचना एक चमत्कार से कम नहीं ।यह कुआं वर्षों से सूखा पड़ा है और पहले भी इसमें एक पडिया गिर गयी थी इसके बावजूद अभी तक इस कुएं को न तो ढंका गया है और न ही सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि यह कुआं भविष्य में और बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है।घटना के बाद अर्क शर्मा को तत्काल इमरजेंसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद, डॉक्टर पी. के. पांडे के यहां की देखरेख में उनका इलाज हुआ। फिलहाल बच्चा खतरे से बाहर है और अपने घर पलहीपुर में सुरक्षित है।गांव में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है और लोग कुएं को ढकने या पक्की बाउंड्री बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

शाहजहांपुर में मीट की बदबू आने पर कांवड़ियों में भड़का गुस्सा, डीसीएम में लगाई आग

आर्यावर्त संवाददाता

शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जिले में बदायूं-फर्रुखाबाद मार्ग पर बृहस्पतिवार तड़के डीसीएम वाहन से मांस की दुर्गंध आने पर कांवड़िये भड़क गए। नाराज कांवड़ियों ने डीसीएम में आग लगा दी। जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कांवड़ियों को शांत कराया। डीसीएम में हड्डी भरी हुई थी।

शिवतेरस पर बृहस्पतिवार सुबह कलान में पटना देवकली मंदिर में कांवड़िये जलाभिषेक करने जा रहे थे। इसी मार्ग पर डीसीएम से दुर्गंध आने पर कांवड़ियों ने रोकने का प्रयास किया। चालक के रोकने के बजाये रफ्तार बढ़ा दी। कांवड़ियों ने उसे किसी तरह रोक लिया। इस बीच चालक मौके से भाग गया। मांस होने की आशंका पर कांवड़ियों ने डीसीएम में आग लगा दी।

कुछ देर में पूरी डीसीएम जल गई। सूचना पर कलान और परौर

थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और कांवड़ियों को शांत किया। इसके बाद डीसीएम को किनारे खड़ा करा दिया है। लोगों में आक्रोश था कि तीन थाना क्षेत्रों को पार कर वाहन कैसे इस रूट में आया था। पुलिस ने लोगों को शांत कराया।

सीओ जलालाबाद अजय राय का कहना है कि तेज रफ्तार से वाहन चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद अज्ञात लोगों ने वाहन में आग लगा दी। वाहन में भैंस के सींग भरे थे। पुश चिकित्सक से कराई जांच में इसकी पुष्टि हुई है।

बल्दीराय तहसील में भ्रष्टाचार चरम पर अधिवक्ताओं ने राजस्व परिषद से शिकायत करके जांच कराए जाने की मांग

सुलतानपुर। तहसील बल्दीराय के अधिकारी की कार्य शैली किसी न किसी मामले को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है कई बार शिकायत होने के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी निस्तारण करने के प्रति अपना मुख मोड़ लेते है ऐसे में अधिकारियों की कार्य शैली पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। अधिवक्ताओ द्वारा राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश से की गई शिकायत में नायब तहसीलदार गुलाब सिंह, आरके सुरेश वर्मा व उनके प्राइवेट दलालों पर रिश्वतखोरी, फाइल दबाने, आदेश में देरी और रिकॉर्ड में हेराफेरी के गंभीर आरोप लगे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि बिना अवैध धन दिए न तो आदेश होते हैं और न ही खतौनी में अंकन। कई महत्वपूर्ण फाइलें रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है पट्टा आवंटन में हेराफेरी और दलालों की खुली छूट का गंभीर आरोप लगा है।

पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत

स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में पीएसआई इंडिया व केनव्यू के सहयोग से आयोजित की गयी थी प्रतियोगिता

आर्यावर्त संवाददाता

बदायूं। डायरिया रोको अभियान के तहत पीएम श्री कम्पोजिट विद्यालय आमगांव ब्लाक-जगत और राजकीय महाविद्यालय आवास-विकास, बदायूं में आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को बृहस्पतिवार को कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जावेद हुसैन ने सीएमओ कार्यालय में पुरस्कृत और सम्मानित किया। यह प्रतियोगिता गत दिनों स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू के सहयोग से आयोजित की गयी थी।

"डायरिया से डर नहीं" विषय पर आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को डायरिया से सुरक्षित बनाने का संदेश जन-जन तक पहुँचाना था। इसके माध्यम से डायरिया के लक्षण, बचाव व

उपचार के बारे में जानकारी प्रदान की गयी थी। पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय आमगांव में आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहीं प्राची, दूसरे स्थान पर रहीं प्रतिज्ञा और तीसरे स्थान पर रहे प्रांशु को आज पुरस्कृत व सम्मानित किया गया। इसके साथ ही राजकीय महाविद्यालय आवास-विकास में आयोजित प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहीं भव्या मौर्या, दूसरे स्थान पर रहीं सुरभि भारती और तीसरे स्थान पर रहीं शिवानी को भी पुरस्कृत और सम्मानित किया गया।

इस मौके पर एसीएमओ (आरसीएच) डॉ. राजवीर सिंह राठौर, एसीएमओ डॉ. श्रीमोहन झा, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी (डीआईओ) डॉ. मो. असलम, डॉ. मो. तहसीन, डॉ. निरंजन सिंह, डॉ. पवन कुमार, डॉ. अमित रस्तोगी, डिप्टी सीएमओ डॉ. पवन जायसी, कमलेश शर्मा जिला प्रोग्राम मैनेजर, अरविंद कुमार राणा जिला कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर, उमेश राठौर अर्बन हेल्थ को आर्डिनेटर, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन से अभय सिंह राठौर, संतोष और पीएसआई इंडिया से शशांक दुबे व दानिश वर आदि उपस्थित रहे।

बिना शपथ लिए ग्राम प्रधान मनोनीत करने के प्रयास पर आपत्ति

सुलतानपुर। विकास खंड बल्दीराय के ग्राम पंचायत रैंचा में ग्राम प्रधान के निधन के बाद गांव में बिना शपथ लिए ग्राम प्रधान मनोनीत करने के प्रयास का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में गांव के निवासी राजेश कुमार यादव ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र देकर फर्जी तरीके से ग्राम प्रधान बनाए जाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।पत्र में कहा गया है कि ग्राम प्रधान बिंद्रा प्रसाद यादव का निधन 21 अप्रैल 2025 को हो गया था। इसके बाद पूर्व प्रधान के पुत्र अरविंद यादव गांव के निर्वाचित सदस्यों को एकत्र कर स्वयं को ग्राम प्रधान मनोनीत करवाने का प्रयास कर रहे हैं,जबकि अभी तक किसी भी सदस्य ने शपथ ग्रहण नहीं किया है और न ही किसी बैठक में हिस्सा लिया है। साथ ही अरविंद यादव स्वयं भी शपथ नहीं लिए हैं।शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि अरविंद यादव द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर कार्यरत ग्राम पंचायत सदस्य नीलू पुत्री अरविंद कुमार का इस्तीफा भी जबरन लिया गया है।

टूट गई थी शख्स की रीढ़ की हड्डी, नहीं थे इलाज के पैसे, दर्द सहन नहीं कर पाया तो रेत डाला खुद का गला

आर्यावर्त संवाददाता

बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तिंदवारी थाना क्षेत्र के भहरौरा गांव में एक युवक ने इलाज के लिए कथित तौर पर पैसे न होने के कारण सुसाइड कर लिया। युवक ने धारदार हथियार से खुद का गला रेत लिया था। उसे घरवाले तत्काल अस्पताल में इलाज के लिए ले गए, लेकिन तबतक उसकी मौत हो गई थी। मृतक का नाम राजेंद्र है।

दिल्ली में शटरिंग का काम करने वाले 45 वर्षीय राजेंद्र की रीढ़ की हड्डी 10 जुलाई को एक दुर्घटना में टूट गई थी। राजेंद्र के बड़े भाई भगीरथ ने बताया कि राजेंद्र पिछले 15 वर्षों से दिल्ली में शटरिंग का कार्य कर रहा था। हादसे के दिन काम करते वक्त उस पर शटरिंग का भारी मलबा गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर में चार टांके आए और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी।

साथी मजदूरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया।

घरवाले बोले- ठेकेदार ने इलाज का पूरा खर्च उठाने का किया था वादा

भगीरथ और उसकी पत्नी अगले ही दिन दिल्ली पहुंचे और ठेकेदार से मिले। घरवालों का आरोप है कि ठेकेदार ने इलाज का पूरा खर्च उठाने और आर्थिक सहायता का वादा किया, लेकिन एक सादे कागज पर अंगूठा लगवाने के बाद कोई मदद नहीं की। मजबूरी में परिवार राजेंद्र को दिल्ली से बांदा लेकर आया और रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।

राजेंद्र का लगभग 25 दिन तक इलाज चला, लेकिन इलाज में भाई के पास मौजूद पैसे और भगीरथ की जमा-पूंजी खत्म हो गई। जब इलाज का खर्च उठाना संभव नहीं रहा, तो उसे तीन दिन पहले घर लाना पड़ा। घर पर दर्द से तड़पते राजेंद्र की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वह चलने-फिरने और उठने-बैठने में असमर्थ था। मंगलवार को दर्द असहनीय हो गया और उसने ब्लेड से अपना गला रेतकर आत्महत्या कर ली। भगीरथ ने बताया कि जब वह और उनकी पत्नी घर लौटे, तो देखा कि राजेंद्र खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

रातभर दर्द से कराहता रहता था

राजेंद्र की भाभी ने बताया कि वह बेहद सीधा और शांत स्वभाव का था। दो बीघा जमीन उसके नाम थी। हादसे के बाद से वह ना के बराबर खा-पी रहा था और रातभर दर्द से कराहता रहता था। कुरसेज चौकी प्रभारी रोशनी सेंगल ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रक्षाबंधन से पहले सुल्तानपुर में मिठाई दुकानों पर सैंपलिंग तेज

सुलतानपुर। रक्षाबंधन के मद्देनज़र खाद्य सुरक्षा विभाग सुल्तानपुर में सतर्क हो गया है। त्योहार पर मिलावटी मिठाइयों की आशंका को देखते हुए विभाग ने शहर के कई मिष्ठान भंडारों पर छापेमारी की। इस दौरान शहर के अवंतिका रेस्टोरेंट से कराची हलवा, दो प्रकार की बर्फी और छेना तथा अन्य दुकानों से कई प्रकार की मिठाइयों के सैंपल लिए गए।

छापेमारी टीम में सहायक आयुक्त खाद्य अजीत कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप यादव (सदर), अभय प्रताप सिंह (नगर पालिका), मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी निर्भय नारायण सिंह और मृदुल कुमार, रमाकांत सिंह शामिल रहे। सभी सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। वहीं विभाग ने लोगों से अपील की है कि मिठाई खरीदते समय ब्रांड और गुणवत्ता पर ध्यान दें।

सुरक्षा एवं संरक्षण के संकल्प के साथ मनाएं रक्षाबंधन पर्व

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। सरस्वती विद्या मन्दिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ज्ञान कुंज विवेकानन्द नगर में रक्षा बन्धन उत्सव कार्यक्रम पारंपरिक ढंग से आयोजित किया गया। उक्त अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्या भारती काशी प्रान्त के प्रदेश निरीक्षक श्री शेषधर द्विवेदी ने कहा कि रक्षा बन्धन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है।यह सम्पूर्ण श्रावण मास भगवान शिव जी यानि प्रकृति को समर्पित है। सभी बहनें अपने छोटे बड़े भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर उनका आशीर्वाद लेकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती हैं। इसी के साथ यह पर्व मनाने का दूसरा प्रमुख उद्देश्य प्रकृति की सुरक्षा एवं संरक्षण हैं। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों और शिक्षकों से आग्रह किया कि सभी लोग एक एक वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर उसकी सुरक्षा एवं संरक्षण का संकल्प लें।

विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश मणि त्रिपाठी जी ने रक्षा बन्धन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सनातन संस्कृति के वैशिष्ट्य से युक्त ये पर्व हमारी धार्मिक धरोहर हैं। जिनके बल पर हमारे नैतिक मूल्य और परंपराएं आज भी जीवित हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉ जे पी सिंह ने की । उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन की प्रशंसा करते हुए सबको आशीर्वचन प्रदान किया। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि जिला प्रचारक श्रीमान् आशीष जी, शिशु मन्दिर के प्रधानाचार्य ब्रह्मनारायण शुक्ल,प्रान्तीय कार्यालय प्रमुख श्रद्धानन्द जी एवं सभी अतिथियों एवं उपस्थित सभी भैयाजी को आचार्या दीदियों, एवं बहनों ने रक्षासूत्र बांधकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। विद्यालय की सभी बहनों ने राखी निर्माण प्रतियोगिता में भाग लिया।बहनों के द्वारा निर्मित रंग बिरंगी अनोखी राखियों की प्रदर्शनी की अतिथियों द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गई।

बुंदेलखंड में कैसे 'साइलेंट किलर' बन रहा फैटी लिवर? रिपोर्ट में हुआ डरा देने वाला खुलासा

आर्यावर्त संवाददाता

बुंदेलखंड। त्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों के लिए नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD)एक नई स्वास्थ्य चुनौती बनकर फिर उभर कर सामने आई है। यह रोग धीरे-धीरे, बिना स्पष्ट लक्षणों के शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाता है और जब तक इसकी पहचान होती है, तब तक यह गंभीर स्तर पर पहुंच चुका होता है। स्थानीय मेडिकल कॉलेज की ओर से किए गए रिसर्च में यह सामने आया है कि क्षेत्र में इस बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

शोधकर्ताओं ने बताया कि इस बीमारी की प्रमुख वजहें बेतरतीब दिनचर्या, अनियमित खानपान, मादक पदार्थों का सेवन, तथा फास्ट फूड की अधिकता बताई जा रही है। बुंदेलखंड के ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों की जीवनशैली में तेजी

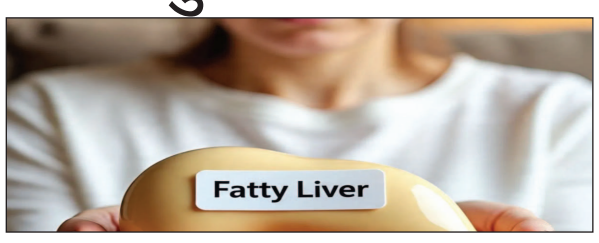

से बदलाव आया है, जिसमें शारीरिक मेहनत की जगह निष्क्रियता और पौष्टिक भोजन की जगह तैलीय व जंक फूड ने ले ली है।

क्या बोले डॉक्टर?

मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ। कुलदीप चंदेल ने बताया कि NAFLD की स्थिति में लिवर में चर्बी जमा होने लगती है, जिससे शरीर में एसजीओटी और एसजीपीटी नामक एंजाइमों का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। ये एंजाइम इस बात का संकेत हैं कि व्यक्ति के शरीर में लिवर या हृदय की कोशिकाएं प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में व्यक्ति को पाचन संबंधी दिक्कतें, मधुमेह, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल जैसी परेशानियां घेर लेती हैं।

डॉ. चंदेल ने बताया कि इस रोग के शुरुआती संकेत इतने हल्के होते हैं कि मरीज उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। परंतु जब रोग बढ़ता है, तब शारीरिक थकावट, पेट में दर्द, और भूख में कमी जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं। इन लक्षणों को यदि व्यक्ति के द्वारा समय रहते गंभीरता से न लिया जाए, तो व्यक्ति को लिवर सिरोसिस जैसी जानलेवा स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है।

रिसर्च में 80 प्रतिशत लोगों में फैटी लीवर

बुंदेलखंड के झांसी में मेडिकल कॉलेज की ओर किए गए एक वर्ष लंबे शोध में 302 मरीजों की जांच की गई तो नतीजों ने चौंकाने वाला सच उजागर किया 80 प्रतिशत मोटे लोगों में फैटी लिवर पाया गया। वहीं, 46 फीसदी डायबिटिक मरीज, 66 फीसदी उच्च कोलेस्ट्रॉल से ग्रसित व्यक्ति, और 40 प्रतिशत थायराइड व ब्लड प्रेशर के रोगी इस बीमारी से पीड़ित पाए गए।

इस Alarming स्थिति से बचने के लिए विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि नियमित स्वास्थ्य जांच कराना भी अति आवश्यक है। खासतौर पर पेट संबंधी समस्याओं या पहले से किसी गंभीर रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। फैटी लिवर की पुष्टि होने पर डॉक्टरी परामर्श के अनुसार चिकित्सा लेना, और दिनचर्या में बदलाव लाना लोगों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है।

इसके लिए दिन की शुरुआत होते ही सबसे पहले योग, प्राणायाम और हल्की कसरत से करनी चाहिए। भोजन में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों, फाइबर युक्त अनाज, और कम वसा वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साथ ही शराब और तली-भुनी चीजों से दूर रहना बेहद जरूरी है। बुंदेलखंड की यह बदलती स्वास्थ्य तस्वीर एक चेतावनी भी है कि यदि समय रहते सचेत नहीं हुए, तो आने वाले वर्षों में यह "साइलेंट किलर" अनेक परिवारों की शांति भी छीन सकता है।

नोएडा ने बनेगा Zero Shape स्काईवॉक, दिल्ली वालों को भी मिलेगा इससे फायदा

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। नोएडा के सेक्टर-62 में अब स्काईवॉक बनने जा रहा है। यह स्काईवॉक दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पास बनेगा, जहां रो दिल्ली से सटे नोएडा में अब 43 करोड़ की लागत से शानदार स्काईवॉक बनने जा रहा है। इसकी डिजाइन फाइनल हो चुकी है। अब जल्द ही इसका टेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। यह नोएडा के सेक्टर-62 में बनने वाला यह स्काईवॉक 530 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा होगा। इससे न सिर्फ नोएडा, बल्कि कई जिलों को फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट को 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है।

यह स्काईवॉक दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पास बनेगा, जहां रोजाना भारी ट्रैफिक रहता है। इस इलाके में पैदल चलने वालों के लिए रास्ता पार करना मुश्किल होता है, क्योंकि सड़क पर गाड़ियां बहुत तेज चलती हैं। कई लोग सड़क पर ही चलते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। इस स्काईवॉक से पैदल यात्रियों को सुरक्षित रास्ता मिलेगा। इसमें नोएडा की तरफ दो एस्केलेटर और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के कोनों पर दो लिफ्ट लगाई जाएंगी, ताकि बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को भी आसानी हो।

स्काईवॉक का डिजाइन जीरो शेप में है। इसे लोहे की छत से ढका जाएगा, ताकि बारिश और धूप में भी लोग आराम से चल सकें। यह स्काईवॉक पास के मौजूदा फुट ओवरब्रिज से भी जुड़ेगा, जिससे गाजियाबाद से नोएडा आने वाले लोग आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। दरअसल, सेक्टर-62 नोएडा का एक बड़ा कॉमर्शियल और शैक्षिक केंद्र है। यहां कई आईटी कंपनियां, कॉलेज और मेट्रो स्टेशन हैं। सुबह और शाम के समय यहां भारी जाम लगता है।

इस स्काईवॉक के बन जाने से पैदल चलने वालों को सड़क पार करने में आसानी होगी और ट्रैफिक भी कम होगा। नोएडा प्राधिकरण के जनरल मैनेजर एसपी सिंह की मानें तो यह स्काईवॉक सेक्टर-62, 63 और छिजारसी जैसे इलाकों में आने-जाने वालों के लिए बहुत मददगार होगा।

यह प्रोजेक्ट नोएडा प्राधिकरण की एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसमें सेक्टर-62 से ममूरा तक 3.15 किलोमीटर लंबा एक मॉडल रोड बनाया जा रहा है। इस रोड पर फुटपाथ, पार्किंग और यू-टर्न को बेहतर करने का काम भी होगा। इसके अलावा, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पास एक खास ऑटो स्टैंड बनाया जाएगा, ताकि ऑटो की वजह से जाम न हो। इस स्काईवॉक से न सिर्फ पैदल यात्रियों को फायदा होगा, बल्कि सड़कों पर गाड़ियों का दबाव भी कम होगा।

गरीब बच्चों का विदेश में पढ़ने का सपना होगा पूरा, दो निजी विवि को हरी झंडी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश के गरीब-मेधावी छात्रों का विदेश में पढ़ाई का सपना भी पूरा होगा। उच्च शिक्षा विभाग यूके के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री (पीजी) करने के लिए छात्रवृत्ति देगा। इसके लिए बृस्पतिवार को कैबिनेट ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेई- चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को हरी झंडी दे दी है। इसे वर्तमान सत्र से ही लागू किया जाएगा।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि योजना के तहत हर साल पांच गरीब व प्रतिभावान छात्रों को एक विषय में मास्टर डिग्री की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह योजना प्रदेश सरकार व द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (एफसीडीओ) के साथ किए गए एमओयू के तहत चलाई जाएगी। इसके तहत प्रति छात्र 23 लाख रुपये की सहायता राज्य सरकार देगी। बाकी का खर्च एफसीडीओ वहन करेगा।

मंत्री ने बताया कि योजना में छात्र-छात्राओं के शिक्षण शुल्क के साथ, परीक्षा व शोध शुल्क, एक छात्र के रहने के लिए खर्च, एक बार आने-जाने का हवाई जहाज का किराया भी इस छात्रवृत्ति में शामिल होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ देने के लिए छात्रों से आवेदन लिए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग और एफसीडीओ आवेदन पत्रों के आधार पर गरीब व मेधावी छात्रों का इसके लिए चयन करेगी।

उन्होंने बताया कि यह योजना शैक्षिक सत्र 2025-26 से शुरू होगी और तीन शैक्षिक सत्रों 2028-29 तक चलेगी। 30 मार्च 2028 के बाद इसके संचालन के लिए एमओयू का नवीनीकरण किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि यह योजना गरीब व मेधावी छात्रों के लिए उनका सपना पूरा करने वाली होगी। क्योंकि काफी मेधावी छात्र आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से भी विदेश में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अब उन्हें इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

बाराबंकी व मथुरा में निजी विवि के संचालन को हरी झंडी

प्रदेश में दो नए निजी विश्वविद्यालयों के संचालन व एक निजी विवि की स्थापना को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इसमें बाराबंकी व मथुरा में विश्वविद्यालय में पढ़ाई की शुरुआत होगी। जबकि मुजफ्फरनगर में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि कैबिनेट ने बोधिसत्व विश्वविद्यालय, बाराबंकी को संचालन प्राधिकार पत्र जारी करने पर सहमति दी है। यह विश्वविद्यालय गदिया, नवाबगंज में 25.31 एकड़ भूमि पर बना है। इसी क्रम में केडी विश्वविद्यालय, मथुरा की स्थापना राजीव मेमोरियल एकेडेमिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अकबरपुर, छाता में 50.54 एकड़ भूमि पर की गई है। इसके संचालन प्राधिकार-पत्र जारी करने को कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। इसी क्रम में वेदांता विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर की स्थापना फतेह चंद चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हुसैनपुर बोपाडा, खतौली में 23.3349 एकड़ भूमि पर की जाएगी। इसको विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय-पत्र जारी किए जाने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मंत्री ने बताया कि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से युवाओं को उनके ही जिले में उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। प्रदेश सरकार हर जिले में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लक्ष्य पर काम कर रही है।

होर्डिंग व प्रचार-प्रसार के लिए अब 15 साल का दिया जाएगा ठेका

प्रदेश सरकार ने शहरों में आकाश चिह्न और विज्ञापन लगाने का लाइसेंस देने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। इन कार्यों का ठेका अब 15 साल के लिए दिया जाएगा। अब तक यह ठेका सिर्फ दो ही साल के लिए दिया जाता था। व्यवस्था बदलने के लिए सरकार ने उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 305 में संशोधित कर दिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैनिबेट ने मंजूरी दे दी है।

किराये पर देने के नाम पर एक लाख रुपये लिए नही दी चाभी

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में एक व्यक्ति ने फैल्ट किराये पर देने के नाम पर महिला से एक लाख रुपये ठग लिए। पैसा लेने के बाद चाभी नहीं दी। परेशान होकर महिला ने सुशान्त गोल्फ सिटी थाने पहुंच कर मुकदमा दर्ज कराया।

पीड़ति समीक्षा सिंह निवासी शाहजहांपुर ने बताया कि ब्रोकर दिव्या सिंह के माध्यम से ओमेक्स हजरतगंज (न्यू) यूनिट किराये पे लेने के लिए दिखाया था जिसको फाइनल करने के लिए दिव्या ने यूनिट के मालिक समीर कुमार श्रीवास्तव निवासी-1402 टावर 18, ओमेक्स रेजीडेसी 2-अर्जुनगंज, लखनऊ से मिलवाया ओमेक्स में 1224 कमरा नं0 में उन्होने बाताया कि में मालिक हूँ इन दोनो यूनिट का और दिव्या के माध्यम से मैने समीर श्रीवास्तव (बिक्की) के खाते में एक लाख रू0 पेमेंट भेज दिया। पीड़ता का आरोप है कि मार्च में पैसा लेने के बाद चाभी देंने में आनाकानी करने लगा।

अनियत्रित कार डिवाइडर से टकराकर बुलेरो में मारी टक्कर, पलटी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। गोसाईंगंज इलाके में एक कार ने लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर बुलेरो को टक्कर मारने के बाद पलट गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगो को बाहर निकाला। इस घटना में कोई हताहत नही हुआ।

गोसाईंगंज पुलिस के मुताबिक अमेठी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत UP 32 ढाबा के पास कार Scross रजिस्ट्रेशन नंबरUP32JP4823 के चालक ब्रिजेश कुमार शर्मा निवासी कासिम बिरुहा थाना गोसाईगंज लखनऊ जो हैदरगढ़ की तरफ से लखनऊ की ओर आ रहे थे जिनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए वाराणसी से लखनऊ की ओर आ रही बुलेरो गाड़ी UP65 DA5455 जिसमे 1. शैलेंद्र पटेल निवासी करोधी थाना चितईपुर वाराणसी, अनिल कुमार कन्नौजिया निवासी शिवपुर थाना शिवपुर वाराणसी की गाड़ी से टकरा गई। जिससे बोलेरो गाड़ी टक्कर लगने से पलट गई और गाड़ी सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। जिसमे किसी प्रकार की कोई जनहानि नही हुई है टक्कर लगने से दोनो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनो पक्षों से कोई तहरीर नही मिली हैं यदि तहरीर मिलतीं है तो उचित कार्यवाईं की जाएगी

फर्जी वेबसाइट बनाकर लाखों की साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, दो आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट की साइबर सेल और थाना सरोजनीनगर पुलिस ने एक अंतरराज्यीय साइबर अपराधी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो शातिर ठगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। यह गिरोह फर्जी वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाकर लोगों को क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने तथा बीमा प्लान के एक्टिव होने का झांसा देकर उनके क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर ऑनलाइन लाखों रुपये की ठगी करता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 25 मोबाइल फोन, 24 सिम कार्ड, एक लैपटॉप, दो राउटर, एक प्रिंटर और ₹41,250 नगद बरामद किया है। इस सफलता के लिए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी ने संयुक्त पुलिस टीम को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया है।मामला तब सामने आया जब 24 जून 2025 को सरोजनीनगर के निवासी जितेंद्र कुमार ने पुलिस को सूचना दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने खुद को बैंक कर्मी बताकर उनसे पैन कार्ड नंबर और ओटीपी मांगकर उनके क्रेडिट कार्ड से ₹1,60,432 की शॉपिंग कर ली। पुलिस ने तुरंत इस मामले में धारा 66D के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। तकनीकी और मैनुअल जांच के बाद टीम ने दिल्ली के मीठापुर स्थित एक मकान पर छापा मारा जहां से राहुल लखेडा और विकास कुमार नामक दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे बैंक के नाम से फर्जी वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाकर लोगों को लिंक भेजते थे। इसके माध्यम से वे क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने या बीमा प्लान के होने का झांसा देते थे। लिंक पर लोग अपनी क्रेडिट कार्ड की पूरी जानकारी भर देते थे, जिससे आरोपियों को ओटीपी सहित सभी संवेदनशील जानकारी प्राप्त हो जाती थी। इसके बाद आरोपियों द्वारा ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डर किया जाता और प्राप्त मोबाइल को बाजार में बिल के साथ सस्ते दामों पर बेचकर वे लाखों की ठगी करते थे।साइबर सेल ने बरामद लैपटॉप और मोबाइल फोन की जांच में पाया कि इनके माध्यम से साइबर ठगी से संबंधित कई शिकायतें ऑनलाइन दर्ज हैं। फिलहाल इन शिकायतों की पुष्टि कर संबंधित मामलों की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त राहुल लखेडा हरियाणा के फरीदाबाद में हत्या, धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में पहले भी अपराधी रह चुका है, जबकि विकास कुमार के आपराधिक इतिहास की जांच जारी है।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दो दिवसीय दौरा कर राहत एवं प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बाढ़ प्रबंधन और राहत कार्यों की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए भदोही, वाराणसी, मऊ एवं जौनपुर जनपदों में दो दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित बस्तियों और मोहल्लों का दौरा कर आम जनता से सीधे संवाद स्थापित किया तथा उनके समस्याओं को सुना और मौके पर ही त्वरित समाधान के निर्देश दिए।मंत्री ने अपने भ्रमण के दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित कीं, जिसमें उन्होंने उनसे क्षेत्र की स्थिति का फीडबैक प्राप्त किया। जौनपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि विद्युत आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक है, लेकिन निचले स्तर के कुछ कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं। इस पर ऊर्जा मंत्री ने अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि वे लापरवाह कर्मचारियों की पहचान कर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।लखनऊ में संबंधित विभागीय अधिकारियों को मंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में जलस्तर घटने के बाद युद्धस्तर पर सफाई अभियान चलाने और विद्युत आपूर्ति को शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी राहत एवं पुनर्वास कार्यों की दैनिक प्रगति की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाए। क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर, तार और पोल की मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर कराए जाने के साथ-साथ बिजली से जुड़े सभी खतरों से बचाव हेतु सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए।मंत्री ए.के. शर्मा ने स्पष्ट किया कि सरकार हर हाल में जनता के साथ खड़ी है और प्रत्येक प्रभावित परिवार तक राहत एवं मदद पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को टीम भावना, संवेदनशीलता और तत्परता के साथ राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से अमल में लाने के निर्देश भी दिए।

संक्षेप

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के आरोपी ऑटो चालक भानू यादव गिरफ्तार

लखनऊ। थाना मड़ियांव पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ शारीरिक शोषण के आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान भानू कुमार यादव पुत्र गंगाराम यादव निवासी नेवादा, थाना इंटौजा, लखनऊ के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 23 वर्ष है और वह ऑटो चालक है।पुलिस के अनुसार, 17 जुलाई 2025 को एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को सुहेल नामक युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। इस मामले में सुहेल, उसकी चाची निशा और उसकी मां के खिलाफ अपहरण, शारीरिक शोषण और धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, विवेचना के दौरान इन तीनों की भूमिका संदिग्ध पाई गई और मुख्य आरोपी के रूप में भानू यादव का नाम सामने आया।6 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम भिठौली तिराहे पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान भानू यादव को उसके थ्री व्हीलर (UP32 YN 8434) समेत गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने उसे संबंधित धाराओं में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।गिरफ्तारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन किया गया। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य थानों व जनपदों से भी जुटाई जा रही है। पुलिस टीम में व0उ0नि0 मो. माजिद फारुकी, उ0नि0 मु. रफअतउल्लाह और महिला आरक्षी पुष्पा सिंह शामिल रहे।

37 मुकदमों में वांछित कुख्यात हिस्ट्रीशीटर 'हुक्की' गिरफ्तार

लखनऊ। राजधानी की पुलिस ने बुधवार को अपराध के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और फरार वारंटी अपराधी राज हुसैन उर्फ हुक्की को गिरफ्तार कर लिया। अपराध की दुनिया में 'हुक्की' के नाम से बदनाम इस अपराधी पर हत्या के प्रयास, डकैती, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, एनडीपीएस और विस्फोटक अधिनियम समेत कुल 37 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। लंबे समय से फरार चल रहे इस अपराधी की गिरफ्तारी पुलिस की अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की नीति का हिस्सा है।पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के पश्चिमी जोन के तहत यह कार्रवाई 7 अगस्त को सुबह करीब 11:40 बजे की गई। प्रभारी निरीक्षक ओमवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में ठाकुरगंज पुलिस टीम ने उसे उसके घर – शल्लू शाह की तकिया, मुफ्तीगंज – के बाहर से दबोचा। आरोपी के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, लखनऊ द्वारा 2015 के एक हत्या प्रयास के मामले में जारी किया गया था।

लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता: चोरी हुई लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के उत्तरी जोन अंतर्गत थाना रहीमाबाद पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए लाइसेंसी रिवॉल्वर चोरी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई रिवॉल्वर, 5 जिंदा कारतूस और ₹6600 नगद बरामद किए हैं। अभियुक्त के खिलाफ पहले से ही थाना रहीमाबाद में मामला दर्ज था, जिसकी विवेचना के क्रम में यह गिरफ्तारी हुई है।थाना रहीमाबाद पुलिस टीम 7 अगस्त को सुबह गहदो बाजार क्षेत्र में गश्त पर थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त खगेश्वर खेड़ा-उमरावल तिराहा रोड पर मौजूद है। इस सूचना पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने कटियारा फार्म के पास स्थित सदन मार्केट की टिनशेड के पास से अभियुक्त को घेरकर गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान विकास पुत्र हरिश्चंद्र रावत, निवासी ग्राम गुलरहिया, मजरा रहटा, थाना रहीमाबाद, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 22 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने सुबह लगभग 3:35 बजे उसे विधिक रूप से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर (संख्या FG27455), पांच जिंदा कारतूस (32 बोर), ₹6600 नकद और एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन (रियलमी 12) बरामद हुआ।गिरफ्तारी के पश्चात पुलिस ने धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

लखनऊ नगर निगम ने डेंगू-मलेरिया रोकथाम को तेज़ किया अभियान, ड्रोन से हो रहा एंटी लार्वा छिड़काव

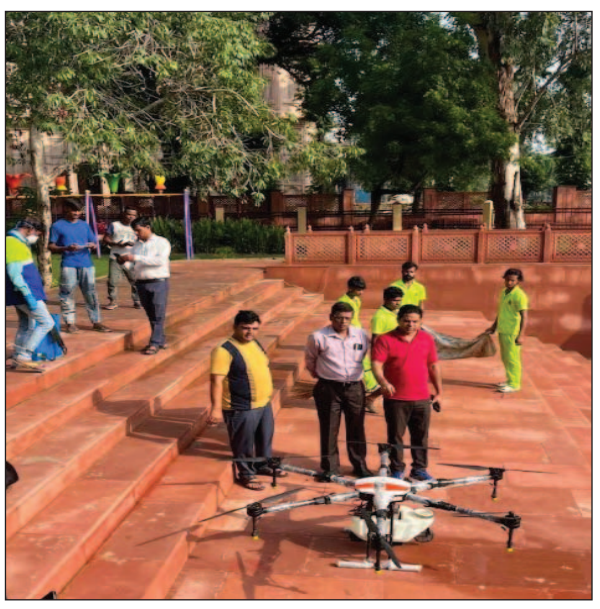

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मानसून के मौसम में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे संचारी रोगों के फैलाव की आशंका को देखते हुए लखनऊ नगर निगम ने रोकथाम अभियान को और तेज़ कर दिया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर शहर भर में फॉगिंग, एंटी लार्वा दवा के छिड़काव और जागरूकता गतिविधियां निरंतर चलाई जा रही हैं।नगर निगम की टीमें विशेष रूप से उन इलाकों में सक्रिय हैं जहां जलभराव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे स्थानों की पहचान कर वहां तत्काल एंटी लार्वा दवा का छिड़काव कराया जा रहा है ताकि मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सके। इसके साथ ही, निगम के पब्लिक एड्रेस सिस्टम और कूड़ा कलेक्शन वाहनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन से एंटी लार्वा छिड़काव कराया जा रहा है। गुरुवार को जोन-1 के बटलर पैलेस झील और जोन-2 की मोती झील पर ड्रोन के माध्यम से दवा का छिड़काव किया गया। इस दौरान दोनों जोनों के अपर नगर आयुक्त ललित कुमार और अरुण कुमार गुप्त ने कार्य का निरीक्षण भी किया।नगर आयुक्त गौरव कुमार और नगर स्वास्थ्य अधिकारी पी.के. श्रीवास्तव ने सभी जोनल सेनेटरी ऑफिसरों और एसएफआई को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे स्थलों की पहचान करें जहां मैन्युअल छिड़काव संभव नहीं है और वहां ड्रोन से दवा का छिड़काव प्राथमिकता पर कराएं।नगर निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने घरों और आसपास पानी जमा न होने दें, कूलर आदि की नियमित सफाई करें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। निगम का कहना है कि जनसहयोग से ही संचारी रोगों की रोकथाम संभव है।

इंद्रा नहर में डूबे युवक का शव गोसाईंगंज इलाके में मिला

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में मंगलवार को इंद्रा नहर में डूबे युवक का शव गुरुवार को गोसाईंगंज इलाके में नहर में उतराता पुलिस को मिला। दो दिनों से एसडीआरएफ टीम नहर में शव की तलाश कर रही थी। सूचना मिलने के बाद उसे बाहर निकाल कर सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम को भेज दिया।

जानकारी के मुताबिक गोसाईंगंज क्षेत्र के अमेठी कस्बे का रहने वाला मोहम्मद शादाब मंगलवार की शाम इंद्रा नहर में नहाने के दौरान उसी में डूब गया था। जिसकी तलाश मंगलवार को स्थानीय गोताखोरों द्वारा को गई थी लेकिन अंधेरा हो जाने व नहर में पानी का अधिक बहाव होने के चलते उसका कुछ पता नही चल सका था। इसके बाद बुधवार को मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम भी पूरे दिन नहर में शादाब की तलाश करती रही लेकिन देर शाम तक उसका कुछ पता नही चल सका। गुरुवार को तेज बहाव के कारण शव गोसाईंगंज क्षेत्र के उदवत खेडा गांव के पास उतराता मिला।

राज्यसभा में प्रमोद तिवारी का हमला : अमेरिका का टैरिफ बढ़ाना अनुचित, पीएम मोदी की चुप्पी देश के गौरव पर सवाल

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को अनुचित और अस्वीकार्य करार दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक भारी टैरिफ लगाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के सामने राष्ट्रीय हितों पर लगातार चुप्पी का नतीजा है। प्रमोद तिवारी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका के सामने उनकी खामोशी से पूरे देश का गौरव धूमिल हो रहा है।प्रमोद तिवारी ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रहित सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता का एजेंडा रहा है और उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि आखिर वे अमेरिकी भयादोहन के सामने अपनी चुप्पी का राज क्यों नहीं बता पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के गौरवशाली अतीत को याद करना चाहिए और इंदिरा गांधी के उस दौर की नीति से प्रेरणा लेनी चाहिए जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति निकसन और विदेश मंत्री सिंगर को कड़े अंदाज में यह समझाया था कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए किसी की परवाह नहीं करता।उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि वे इंदिरा गांधी की समाधि स्थल पर जाकर प्रेरणा लें और देश के हित में एक मजबूत नीति के तहत अमेरिका को उचित जवाब दें। प्रमोद तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 'नमस्ते ट्रंप' के जरिए की गई गलती की कीमत देश को आज अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक नीति पर आ रही आंच से चुकानी पड़ रही है।विपक्ष के उपनेता ने यह भी कहा कि अमेरिका लगातार 33 बार सीजफायर तोड़ने और टैरिफ बढ़ाने जैसी कार्रवाई करके देश की प्रतिष्ठा पर हमला कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय हितों के परिप्रेक्ष्य में दृढ़ता दिखानी चाहिए। उन्होंने इस अनुचित व्यापार दबाव को मोदी सरकार में इच्छाशक्ति की कमी भी बताया।इसके अलावा, प्रमोद तिवारी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर भी मोदी सरकार की आलोचना की और कहा कि सरकार संसद में इस पर चर्चा से कतरा रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग से 65 लाख कटे हुए वोटों के मामले में पूछताछ का उल्लेख करते हुए कहा कि आयोग को 32 लाख लोगों के पलायन का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चुनाव सुधार पर संसद में चर्चा देश का संवैधानिक अधिकार है और निर्वाचन आयोग को लोगों के वोट के अधिकार से छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है।

लखनऊ में ताला तोड़कर चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का भंडाफोड़, 35 लाख के जेवरात बरामद

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में ताला तोड़कर घरों में घुसने और लाखों के आभूषण चुराने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने इस गिरोह के चार शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 35 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण, एक चोरी की मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में लखीमपुर खीरी और लखनऊ के निवासी शामिल हैं। गिरोह बीते कई महीनों से लखनऊ में बंद घरों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था।पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आशियाना थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय पुलिस और क्राइम टीम (डीसीपी मध्य) की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर बुधवार को बीबीएयू विश्वविद्यालय के पास स्थित सर्विस लेन से चार आरोपियों को चोरी की योजना बनाते समय गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान लखीमपुर खीरी निवासी सुधीर कश्यप, गौरव सिंह और मोहम्मद जिसान के साथ-साथ लखनऊ के गोमतीनगर निवासी नमित मिश्रा के रूप में हुई है। पूछताछ में सभी ने कई चोरियों की बात स्वीकार की है और उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में चोरी गया माल भी बरामद किया गया है।पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी सुधीर कश्यप एक कुख्यात अपराधी है, जिस पर लखीमपुर खीरी और लखनऊ के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, चोरी, लूट और मारपीट जैसे गंभीर अपराधों के 11 से अधिक मामले दर्ज हैं। गिरोह का पूरा संचालन सुधीर ही करता था, जो अपने साथियों के साथ मिलकर लखनऊ के अलग-अलग मोहल्लों और कॉलोनियों में बंद पड़े मकानों की रेकी करता था। गिरोह के सदस्य पहले उन मकानों को चिन्हित करते जिनमें ताले लगे होते या जिनमें लंबे समय से कोई हलचल न दिखाई देती। इसके बाद ये लोग दिन या रात के समय मौका देखकर मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ते और घर के भीतर घुसकर पूरी सफाई से कीमती आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर देते थे।गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने इनके ठिकानों से भारी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। बरामद माल में सोने की चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, हार, मांगटीका, ब्रेसलेट, हेयरबैंड, कड़े, मंगलसूत्र आदि शामिल हैं। वहीं चांदी के जेवरों में पायल, चम्मच, थाली, करधनी, बिछिया, चेन, ब्रेसलेट और चांदी की अन्य धातुएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आरोपियों के पास से एक काली स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल चोरी की घटनाओं में किया जा रहा था। बरामद सभी आभूषणों की अनुमानित बाजार कीमत 35 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है।गिरोह की गिरफ्तारी से पुलिस ने कम से कम तीन बड़ी चोरियों का खुलासा किया है, जिनमें आशियाना क्षेत्र के मधुरिमा तिवारी और सत्यदेव राजपूत के घरों में हुई ताले तोड़कर की गई चोरी शामिल है। इसके अलावा गोमतीनगर में एक प्रवासी भारतीय के घर से चोरी की घटना भी इसी गिरोह द्वारा अंजाम दी गई थी। ये सभी घटनाएं पिछले कुछ महीनों में हुई थीं और पुलिस के लिए चुनौती बन गई थीं।पुलिस ने बताया कि यह गिरोह बेहद शातिराना तरीके से काम करता था। चोरी के बाद माल को स्थानीय बाजारों या इंटरस्टेट चैनल के जरिए खपाया जाता था। आरोपी अपने ऊपर शक न हो इसलिए आम लोगों की तरह रहन-सहन रखते थे और लखनऊ में अलग-अलग स्थानों पर किराए के मकानों में रहते थे।इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में आशियाना थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह, निरीक्षक क्राइम ब्रांच, उपनिरीक्षक, सिपाही और तकनीकी टीम के सदस्य शामिल थे। कुल 19 सदस्यीय टीम ने सतर्कता और मुस्तैदी के साथ गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस कमिश्नर लखनऊ ने टीम को उत्कृष्ट कार्य के लिए सराहना दी है।पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। यदि वे किसी भी कारण से लंबे समय तक घर से बाहर जाते हैं, तो पुलिस को सूचना दें और अपने पड़ोसियों को भी सतर्क करें। सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और 'नेबरहुड वॉच' जैसी सामुदायिक निगरानी व्यवस्था को मजबूत करें ताकि अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच रक्षा संवाद के जरिये सामरिक संबंधों में हो गयी नई शुरुआत

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच गहराते रक्षा संबंध न केवल द्विपक्षीय सहयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र की उभरती भू-राजनीतिक चुनौतियों के संदर्भ में भी सामरिक दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक हैं। देखा जाये तो आज की वैश्विक व्यवस्था में, समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, साइबर खतरों और बहुपक्षीय सहयोग जैसे मुद्दों पर साझेदारी का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ीलैंड भले ही भौगोलिक रूप से भारत से दूर हो, परंतु दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्य, मुक्त और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें स्वाभाविक रणनीतिक साझेदार बनाते हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र, जो आज वैश्विक शक्ति संघर्ष का केंद्र बन चुका है, उसमें भारत की भूमिका एक प्रमुख स्थिर कारक के रूप में उभर रही है। वहीं, न्यूज़ीलैंड अपनी शांतिपूर्ण, सहयोगात्मक नीति और समुद्री सुरक्षा में सक्रियता के कारण एक विश्वसनीय साझेदार है। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हम आपको बता दें कि भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच हुई प्रथम रक्षा रणनीतिक वार्ता (Defence Strategic Dialogue) इस बढ़ते सामरिक सहयोग का एक स्पष्ट संकेत है। प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री सूचना साझा करना और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में बातचीत ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को नई गति प्रदान की है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच रक्षा सहयोग केवल रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक सामंजस्य और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। भविष्य में यह सहयोग दोनों देशों के लिए सामरिक संतुलन और वैश्विक नेतृत्व के अवसरों को और सुदृढ़ कर सकता है।

हम आपको बता दें कि 05 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली में भारत-न्यूज़ीलैंड रक्षा रणनीतिक वार्ता (Defence Strategic Dialogue) का पहला संस्करण आयोजित किया गया। यह न केवल दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को गहराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उभरती सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में एक नए रणनीतिक तालमेल की शुरुआत भी मानी जा सकती है। इस संवाद की सह-अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) अमिताभ प्रसाद और न्यूज़ीलैंड रक्षा मंत्रालय की अंतरराष्ट्रीय शाखा की प्रमुख मिस कैथलीन पियर्स ने की। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा और रक्षा उद्योग में साझेदारी को सशक्त करने, बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करने, ग्लोबल कॉमन्स (जैसे कि समुद्री क्षेत्र, साइबर स्पेस आदि) से संबंधित मुद्दों पर सामंजस्य बढ़ाने और White Shipping Information Exchange के माध्यम से सूचना साझा करने की प्रक्रिया को और मजबूत करने पर चर्चा की।

इसके अलावा, भारत ने न्यूज़ीलैंड की CTF-150 (Combined Task Force-150) की सफल कमान संभालने के लिए सराहना की, जिसमें भारतीय नौसेना के पाँच जवान भी स्टाफ के रूप में तैनात थे। यह तथ्य दोनों देशों के बीच अंतर-संचालन और विश्वास का प्रतीक है। हम आपको याद दिला दें कि मार्च 2025 में दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके अंतर्गत यह संवाद स्थापित किया गया। इस MoU ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को औपचारिक और संस्थागत रूप प्रदान किया है। देखा जाये तो यह वार्ता सिर्फ एक द्विपक्षीय चर्चा नहीं थी, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नवीन शक्ति संतुलन और साझी रणनीतियों के निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। भारत और न्यूज़ीलैंड दोनों ही लोकतांत्रिक मूल्य, खुले समुद्री मार्गों की सुरक्षा, और कानून आधारित वैश्विक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं।

हम आपको बता दें कि राजनयिक और रक्षा सहयोग के साथ-साथ दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, शैक्षणिक और खेल—विशेषकर क्रिकेट—के माध्यम से भी मजबूत संबंध हैं। अगस्त 2024 में भारत के राष्ट्रपति की न्यूज़ीलैंड यात्रा और मार्च 2025 में दोनों प्रधानमंत्रियों की बैठक ने द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊँचाई दी है। बहरहाल, भारत-न्यूज़ीलैंड रक्षा रणनीतिक संवाद एक ऐसा मंच बनकर उभरा है, जो केवल सुरक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक नेतृत्व, क्षेत्रीय स्थिरता, और रणनीतिक लचीलापन की दिशा में भी मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है। यह संवाद दोनों देशों की साझा आकांक्षाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक जिम्मेदारियों का प्रमाण है।

ताकि भगदड़ के हादसों पर लग सके लगाम

भगदड़ की घटनाओं को लेकर अपनी व्यवस्था कितना संजीदा है, इसी साल हुई घटनाओं से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। साल 2025 में ही सात घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें आधिकारिक तौर पर 81 लोगों की जान जा चुकी है।

उमेश चतुर्वेदी

हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ की सुर्खियों की स्याही अभी सूखी नहीं कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से भी भगदड़ की खबर आ गई है। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर देश तेजी से कदम बढ़ा रहा है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि तकनीक और सहूलियतों से देश लैस होता जा रहा है। इस संदर्भ में जब भगदड़ की घटनाएं सामने आती हैं तो आधुनिकता से कदमताल करने वाली ये छवियां दरकने लगती हैं। ऐसा नहीं कि देश का ध्यान इस विरोधाभास की ओर नहीं है। फिर भी ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं। ऐसी घटनाएं जब भी होती हैं तो एहतियाती कदम उठाए जाने की प्रशासनिक तंत्र की ओर से घोषणाएं होती हैं। कुछ दिन में देश ऐसी घटनाओं को भुला देता है। अभी भूलने और भुलाने का यह खेल जारी ही रहता है कि कोई नई घटना आ जाती है और एहतियाती कदमों का ऐलान महज हवा-हवाई बनकर रह जाता है।

भगदड़ की घटनाओं को लेकर अपनी व्यवस्था कितना संजीदा है, इसी साल हुई घटनाओं से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। साल 2025 में ही सात घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें आधिकारिक तौर पर 81 लोगों की जान जा चुकी है। जबकि सैकड़ों घायल हुए हैं। दिलचस्प यह है कि ये घटनाएं कुंभ जैसे भीड़भाड़ वाले सांस्कृतिक और पारंपरिक आयोजन में तो हुई हीं, राष्ट्रीय राजधानी के रेलवे स्टेशन से लेकर गोवा जैसे कम जनसंख्या वाले राज्य में भी घटीं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नई सदी के बाइस साल में 23 बार भगदड़ मची, जिनमें करीब डेढ़ हजार लोगों को जान गंवानी पड़ी। इन घटनाओं में घायल लोगों में से कई दिव्यांग बन गए तो कई को ऐसा मानसिक आघात लगा कि उससे अभी तक उबर नहीं पाए हैं।

भगदड़ की घटनाओं के लिए नागरिक बोध की कमी को पहला कारण माना जाता है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि भगदड़ की ज्यादातर घटनाएं प्रशासनिक तंत्र की खामी की वजह से होती है। मसलन, 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटी घटना की वजह रेलवे अधिकारियों की सोच रही, जिन्होंने आनन-फानन में ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल दिया और उसमें जगह पाने के लिए लोग दौड़ पड़े। दुनिया की बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अधिकारियों का कल्पनाशील और अनुमानशील होना जरूरी माना जाता है। लेकिन भारतीय प्रशासनिक ढांचे इस कल्पनाशीलता की अक्सर कमी नजर आती है। उसे भावी संकटों और समस्याओं का अनुमान लगाने के लिए जरूरी सोच की कमी है। वह किसी समस्या का अंदाजा लगाकर उसे शुरू में रोकने और व्यवस्थित करने की बजाय आखिरी छोर पर निबटने की सोच से लगातार लैस रहता है। मेले-ठेले में जाने वाले लोगों की भीड़ को मेले में घुसने से पहले व्यवस्थित करने और उसे रोकने में भारतीय प्रशासनिक तंत्र की दिलचस्पी कम होती है, लेकिन जब मेले में भीड़ बढ़ जाती है तो मेले वाली जगह के दरवाजे पर वह अचानक से रोक लगा देता है। जबकि होना यह चाहिए कि मेले की ओर जान वाले रास्ते पर भीड़ को देखते हुए रोक लगा दी जाए। दरवाजे पर भीड़ को रोकने से मेले में भीड़ भले ही ना घुसे, लेकिन पीछे से आ रहे रेले पर रोक नहीं लग पाती। इससे बैरिकेट वाली जगह पर भीड़ का दबाव बढ़ जाता है। पीछे वाली भीड़ के दबाव के चलते एक वक्त ऐसा आता है कि बैरिकेट का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर रेला लोगों को धकियाते आगे बढ़ने लगता है। इस बीच कोई गिर गया तो पीछे वाले के पास ना तो इतना वक्त होता है कि वह समझ पाए ना ही इतनी क्षमता कि पीछे वाली भीड़ को रोक पाए। वह सामने गिरे व्यक्ति के शरीर की ओर अपना पैर बढ़ाने से रोक भी नहीं पाता। इसी दौरान गिरे हुए लोग दूसरे लोगों के पांवों से कुचलते चले जाते हैं। प्रयागराज की भगदड़ की भी वजह यही थी। भीड़ पीछे नहीं रोकी गई, स्नान केंद्र के पास रोकी गई। इसकी वजह से बैरिकेट पर दबाव बढ़ा और पीछे से आए रेला ने इसकी परवाह नहीं कि कौन गिरा है और किसके पेट,पीठ या सिर पर उसका पैर पड़ रहा है।

भगदड़ के बारे में एक अवधारणा रही है कि गरीब-गुरबा और अशिक्षित लोग ही इसके शिकार बनते हैं। लेकिन यह अधूरा सच है। यह सच है कि उत्तर भारत के मंदिरों में दर्शनार्थियों की भीड़ में ज्यादार निम्न मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। उत्तर भारत में मंदिरों तक में वीआईपी संस्कृति का बोलबाला है। इसकी तुलना में दक्षिण भारतीय मंदिरों में वीआईपी संस्कृति कुछ कम है। हालांकि दक्षिण के भी कई मंदिरों में दर्शन की व्यवस्था में वीआईपी संस्कृति का तड़का रहता है। लेकिन तुलनात्मक रूप से उत्तर में यह संस्कृति ज्यादा है। इसलिए उत्तर के मंदिरों और धार्मिक मेले-ठेले में अनुशासनहीन भीड़ की बहुलता होती है। चूंकि प्रशासनिक तंत्र कल्पनाशीलता से उन्हें व्यवस्थित नहीं कर पाता, लिहाजा भगदड़ की दुर्भाग्यजनक घटनाएं हो जाती हैं।

इसमें दो राय नहीं कि भारत की एक बड़ी समस्या भारत की बड़ी जनसंख्या भी है। हालांकि आज की राजनीति का एक हिस्सा इसे समस्या नहीं मानती। क्योंकि उसका आधार वोट इसी भीड़तंत्र से ही विकसित होता है। भारत में एक बड़ी समस्या यह है कि भीड़ को अनुशासित करने का संस्कार और शिक्षण पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर नहीं है। इसकी वजह से मौका पाते ही हर व्यक्ति रसूख के साथ भीड़ से निकलना चाहता है या फिर अपना वर्चस्ववादी स्वभाव दिखाना चाहता है। प्रशासनिक तंत्र इस मानस के आगे कभी रसूख देख झुक जाता है तो कभी वह सोच भी नहीं पाता कि इसके नकारात्मक असर क्या-क्या हो सकते हैं। ऐसे में कई बार पिछड़ती हुई भीड़ अपना आपा भी खो देती है। भारत का एक बड़ा हिस्सा अरसे तक चूंकि गरीबी की मार झेलता रहा है, इसलिए उसके अवचेतन में कुछ पाने की चाह में दूसरों को पीछे छोड़ने की सोच हावी रहती है। इसमें अगर अफवाह अगर मिल जाती है तो हालात भयावह हो जाते हैं। कह सकते हैं कि संस्कार और सोच की कमी, व्यवस्था को सुचारू बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले तंत्र की कल्पनाहीनता और घनी जनसंख्या का कोलाज के सामने उनके बेपटरी होने की आशंका ज्यादा रहती है। ऐसा जब होता है तो हादसों के रूप में उसका भयावह नतीजा सामने आता है।

ऐसे में सवाल यह है कि क्या ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती कि देश के भीड़भाड़ वाले आयोजन बिना किसी भगदड़ या अव्यवस्था के संपन्न हो सकें। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मुकम्मल नीति बनाने और उसे कड़ाई से लागू करने की जरूरत है। हमें पता है कि आज के दौर की हर कठिन राह को तकनीक नेआसान की है। इसने तमाम समस्याओं के समाधान की नई राहें भी निकाली हैं। नीतिगत स्तर पर प्रशासनिक तंत्र को तकनीक के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाना होगा। प्रशासनिक तंत्र को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाना होगा कि तकनीक के इस्तेमाल से वे ठीक से पता लगा पाएं कि किस बिंदु पर भीड़ को रोका जाना चाहिए, कहां बैरिकेटिंग करके भीड़ को नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रशासनिक तंत्र की सोच में कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए भी तैयार करना होगा। प्रशासनिक तंत्र समस्याओं का अनुमान लगाने वाला मानस विकसित कर सके, इसके लिए भी जरूरी इंतजाम करना होगा। इसके साथ ही, भीड़ को अनुशासित करने के लिए दो स्तरों पर काम करना होगा। स्कूली स्तर से ही इस दिशा में शिक्षा और संस्कार देना होगा। साथ ही, आम लोगों को पीछे छोड़ने या किनारे रखने वाली वीआईपी संस्कृति पर पूरी तरह रोक लगाना भी इस दिशा में बेहद जरूरी कदम होना चाहिए। इसके साथ ही अफवाहों पर लगाम लगाने के मुकम्मल इंतजाम होने चाहिए। तभी जाकर हम आने वाले दिनों में अपनी भीड़ को सुरक्षित और बेहतर आयोजन का उपहार दे पाएंगे।

अजब-गजब

खाने की वजह से महिला को छोड़ना पड़ा अमेरिका, सुनाई शॉकिंग स्टोरी

दुनिया का शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा, जिसे अपने वतन को छोड़ना अच्छा लगता हो। हालांकि कई बार इंसान के पल्ले ऐसी मजबूरी फंस जाती है कि उसे अपना वतन छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। कभी कोई नौकरी की वजह से, तो कभी किसी और कारण से... लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान को सिर्फ खाने की वजह से देश छोड़ना पड़े? सुनने में आपको ये बात अजीब थोड़ी जरूर लग सकती है, लेकिन ये कहानी एकदम सच्ची है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की रहने वाली एक महिला बी (Bee) के साथ ऐसा ही हुआ। उन्हें एक रहस्यमयी एलर्जी थी, जिसकी वजह से उनका शरीर रोज़ नए चकत्तों और गंभीर रिएक्शन से जूझ रहा था। हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने अमेरिका छोड़कर यूरोप में बसने का फैसला किया।

बी को मास्ट सेल एक्टिवेशन सिंड्रोम (MCAS) नाम की दुर्लभ बीमारी है। इसमें शरीर की इम्यून सेल्स बिना कारण ही एक्टिव हो जाती है और ज़्यादा मात्रा में केमिकल छोड़ती हैं। जिससे तेज एलर्जी जैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे खुजली, सूजन, उल्टी, ब्लड प्रेशर गिरना और मानसिक भ्रम...जैसी स्थिती पैदा हो जाती है।

आलम तो ऐसा है कि बी अगर नॉर्मल चीज गेहूं की ब्रेड और यहां तक कि ताज़ी सब्ज़ियां खाती है तो उन्हें ये समस्या देखने को बराबर मिलती है। उनके शरीर की हालत ऐसी हो गई है कि वो लगातार एनाफिलैक्सिस और पेट दर्द जैसी परेशानियों से जूझ रही थीं। नवंबर 2024 में यूरोप शिफ्ट होने से पहले उनका खानपान सिर्फ तीन चीज़ों तक सिमट गया थाः ब्रोकोली, नारियल और चिकन। लेकिन जैसे ही उन्होंने देश बदला, उनका शरीर अलग तरह से रिएक्ट करने लगा।

यूरोप पहुंचकर उन्होंने TikTok पर एक सीरीज़ शुरू की जिसमें वह अमेरिका में एलर्जी देने वाले खाद्य पदार्थों को खाकर दिखाती हैं। एक वीडियो में उन्होंने बताया कि गलती से उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया जिससे पहले गंभीर एलर्जी होती थी, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। बी का मानना है कि अमेरिका में उनकी एलर्जी की असली वजह वहां के खाद्य पदार्थों में मौजूद मायकोटॉक्सिन्स थे, जो फफूंद से निकलने वाले विषैले तत्व होते हैं। ये अक्सर खराब भंडारण और ढीले खाद्य सुरक्षा नियमों की वजह से भोजन में मिल जाते हैं। बी कहती हैं कि यूरोप और कई अन्य देशों में इन टॉक्सिन्स पर कड़ी निगरानी होती है, इसलिए वहां का खाना ज़्यादा सुरक्षित होता है। हालांकि, मशहूर एलर्जिस्ट डॉ। रुबिन ने चेतावनी दी है कि ऐसी गंभीर एलर्जी वाले लोगों को बिना डॉक्टर की देखरेख के खुद से ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह जानलेवा साबित हो सकता है।

ब्लॉग

'आपरेशन सिंदूर' : सिर्फ बहस, जवाब गायब!

- राजेंद्र शर्मा

विपक्ष बेशक खासे प्रभावी तरीके से यह उजागर करने में कामयाब रहा कि राजनीतिक नेतृत्व द्वारा अपनायी गयी सैन्य रणनीति के चलते, इस कार्रवाई के शुरूआती दौर में भारतीय वायु सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा लगता है। याद रहे कि यह सिर्फ विपक्ष का अनुमान नहीं है। सीडीएस समेत विभिन्न शीर्ष सैन्य अधिकारियों द्वारा अलग-अलग मौकों पर की गयी टिप्पणियों से यह स्पष्ट है। आखिरकार, संसद को पहलगाम के बैसरन में आतंकवादियों द्वारा किए गए हत्याकांड से लेकर, उसके बदले के नाम पर छेड़े गए 'आपरेशन सिंदूर' तक पर चर्चा का मौका मिल ही गया। बेशक, इस सिलसिले में यह दर्ज किया जाना जरूरी है कि संसद को बैसरन हत्याकांड के पूरे तीन महीने और ऑपरेशन सिंदूर के भी रोके जाने के करीब ढाई महीने बाद, चर्चा का यह मौका मिला। और राष्ट्रीय सुरक्षा के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद में चर्चा होने में यह विलंब कोई संयोग का या तात्कालिक व्यस्तताओं में समय न मिल पाने का नतीजा नहीं था। यह विलंब मौजूदा सरकार ने सचेत रूप से सुनिश्चित किया था। और इसे सचेत रूप से सुनिश्चित करने में इस मुद्दे पर संसद का 'विशेष सत्र' बुलाए जाने की एकजुट विपक्ष की मांग का ठुकराया जाना ही शामिल नहीं था बल्कि इसका रास्ता बनाने के लिए, एक अनोखी तिकड़म का सहारा लिया जाना भी शामिल था, जिसके तहत अब तक के संसदीय इतिहास में पहली बार, डेढ़ महीने से भी ज्यादा पहले, संसद के आगामी सत्र की तारीखों का ऐलान किया गया था। यह एक प्रकार से 'विशेष सत्र' की विपक्ष की मांग के ठुकराए जाने का भी ऐलान था।

बेशक, अंततः हुई इस चर्चा को इस अर्थ में विस्तृत या विशद चर्चा कहा जा सकता है कि इसमें दोनों सदनों में सभी पक्षों को समुचित समय ही नहीं मिला, सरकार की ओर से शीर्ष स्तर से इस चर्चा का जवाब भी दिया गया। लोकसभा में खुद प्रधानमंत्री ने पौने दो घंटे से भी कुछ ज्यादा लंबा जवाब दिया, जबकि राज्यसभा में मोदी सरकार में व्यवहार में नंबर-दो माने जाने वाले, गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब देने की जिम्मेदारी संभाली। इस बहस में सत्तापक्ष के इस पूरे प्रकरण में 'सफलता' के दावों को जैसे बल प्रदान करने के लिए ही, लोकसभा में इस बहस के शुरू होने से सिर्फ एक दिन पहले, जम्मू-कश्मीर में एक मुठभेड़ में तीन आतंकवादियों को मार गिराया गया था, जिनके संबंध में गृहमंत्री ने पहले लोकसभा को और बाद में राज्यसभा को बताया कि यही तीनों बैसरन के कत्लेआम को अंजाम देने वाले आतंकवादी थे। इस दावे को प्रामाणिक बनाने के लिए गृहमंत्री ने विस्तार से फोरेंसिक लेबोरेटरी की जांच रिपोर्टों के बारे में बताया, जो इसका साक्ष्य प्रस्तुत करती थीं कि अब मारे गए आतंकवादियों की बंदूकों से ही वे गोलियां चली थीं, जिन्होंने बैसरन के घास के मैदान में 26 लोगों की जान ली थी।

यह दूसरी बात है कि पर्यटकों के हत्यारों का, दहशतगर्दी की वारदात के बाद तीन महीने तक गायब रहने के बाद, गृहमंत्री के लोकसभा में भाषण से एक ठीक एक दिन पहले सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारा जाना, सत्तापक्ष के लिए इतना ज्यादा सुविधाजनक संयोग था कि उस पर सहज ही विश्वास नहीं हो सकता था। बहस के दौरान विपक्ष के अनेक सांसदों ने इशारों में और कुछ ने सीधे-सीधे इस संयोग पर सवाल खड़े भी किए। लेकिन, सत्तापक्ष के सभी लक्ष्यों को हासिल करने में 'कामयाबी' के दावों के लिए, इस 'ऑपरेशन महादेव' की कामयाबी का यह दावा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसके महत्व का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि संसद की इस बहस के फौरन बाद, अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी के अपने दौरे पर प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सभा में जोर देकर इसका दावा किया कि 'महादेव के आशीर्वाद से पहलगाम के बदले का अपना वादा उन्होंने पूरा कर दिया है।'

बैसरन से लेकर सिंदूर तक पर संसद में हुई यह बहस लंबी तो जरूर थी, लेकिन जो कुछ हुआ उस पर, उसके कारणों पर और भविष्य के लिए उसके सबकों पर, शायद ही कोई रोशनी डालती थी। संक्षेप में इसकी मूल वजह थी, सत्तापक्ष की हर तरह की जवाबदेही तथा जिम्मेदारी से बचने की कोशिश। इस कोशिश में सत्तापक्ष ने जवाबी हमले के नाम पर शोर तो बहुत उठाया लेकिन, न विपक्ष के माध्यम से उठाए गए देश तथा दुनिया भर के लोगों के सवालों का कोई वास्तविक जवाब दिया और न ही किसी तरह से अपनी जवाबदेही स्वीकार की। बहस की इस दिशा का अंदाजा एक इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री के पौने दो घंटे से भी लंबे भाषण में, विपक्ष तथा खासतौर पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर हमला करने के लिए, देश के पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू का पूरे पंद्रह बार नाम लिया गया। इस बहस में सत्तापक्ष ने अपनी विफलताओं से संबंधित सवालों के जवाब देने के बजाय, विपक्ष की अतीत की कथित विफलताओं पर हमला बोलने की ही रणनीति अपनायी, जो मोदी राज की खास पहचान ही बन गयी है।

बैसरन की जिस आतंकी वारदात से यह पूरी घटनाक्रम शुरू हुआ था, उसके लिए जिम्मेदार सुरक्षा चूक को लेकर, सत्तापक्ष में कोई पछतावा या मलाल होना तो दूर रहा, वह तो खुले मन से सुरक्षा चूक की बात मानने तक को तैयार नहीं था। उसने इसकी जुमलेबाजी के पीछे छुपने की कोशिश जरूर की कि आतंकवादी घुस आए तो सुरक्षा चूक तो होगी ही और हम शासन में हैं तो चूक हमारी ही कही जाएगी! इस तरह का रुख इसके बावजूद था कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से ही निपटने और उसका शेष देश के साथ और पुख्ता तरीके से एकीकरण करने के नाम पर, 2019 के 5 अगस्त को, धारा-370 को निरस्त करने तथा जम्मू-कश्मीर को बांटकर लद्दाख उससे अलग करने तथा उसका राज्य का दर्जा समाप्त कर, उसे केंद्र शासित क्षेत्र बनाने के बाद से, साधारण पुलिस व्यवस्था समेत समूची सुरक्षा व्यवस्था, सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय से संचालित होती है। यहां तक कि पहलगाम की घटना के बाद, जब सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए शीर्षस्थ अधिकारियों की बैठक बुलायी गयी, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लैफ्टीनेंट गवर्नर उसके केंद्र में रहा, जबकि जम्मू-कश्मीर के निर्वाचित मुख्यमंत्री को सचेत रूप से उक्त बैठक से बाहर रखा गया था।

घटना के महीनों बाद, लैफ्टीनेंट गवर्नर ने जिस चलताऊ ढंग से 'सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी' ली थी, उससे रत्तीभर ज्यादा जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने इस बहस के दौरान नहीं दिखाई। यह इसके बावजूद था कि अब तक यह सभी जान चुके हैं कि बैसरन में पहले एक न्यूनतम सुरक्षा मौजूद थी, जिसे घटना से कुछ ही हफ्ते पहले हटाया गया था। और यह भी कि शासन के पास इसकी खुफिया जानकारियां थीं कि आतंकवादी घटना के समय के करीब ही किसी बड़ी कार्रवाई की योजना बना रहे थे और उनके इस बार पर्यटकों को निशाना बनाने की संभावना थी। इस सबके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब देने की कोई कोशिश नहीं की गयी। और इस महत्वपूर्ण सवाल को तो पहचाना तक नहीं गया कि 2019 के अगस्त से जम्मू-कश्मीर के मामले में केंद्र सरकार ने जो नीति तथा दिशा अपनायी है, उसके संबंध में इस तरह की घटनाओं का होना क्या कुछ कहता है? इसी तरह, 'ऑपरेशन सिंदूर' के संबंध में न तो इस सवाल का कोई वास्तविक जवाब दिया गया कि साढ़े तीन दिन की लड़ाई से क्या हासिल हुआ और न ही इस महत्वपूर्ण सवाल का कोई तार्किक जवाब दिया गया कि अगर लड़ाई में भारत वाकई भारी पड़ रहा था, तो अचानक शस्त्रविराम की घोषणा क्यों कर दी गयी? और घोषणा भी सबसे पहले स्पष्टपति ट्रम्प द्वारा और उसके बाद ही दोनों युद्धरत पक्षों, भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के द्वारा की गयी। इस लड़ाई का हासिल क्या रहा, इसके संबंध में सत्तापक्ष के 'सारे लक्ष्य पूरे होने' के अंतहीन दावों के बावजूद, सच्चाई यह है कि इस लड़ाई के वास्तविक परिणामों पर इतनी रोशनी तक नहीं पड़ने दी गयी है कि देश यह जान पाता कि क्या इस कार्रवाई में भारतीय वायु सेना का भी कोई नुकसान हुआ था और अगर हुआ था तो क्या और कितना? रक्षा मंत्री ने परीक्षा में पेंसिल टूटने की मिसाल देकर, इन सवालों को हास्यास्पद बनाने की जो कोशिश की, उसे कोई गंभीरता से कैसे ले सकता है? अपने पक्ष के नुकसान का आकलन किए बिना, किसी कार्रवाई के हासिल का आकलन किया ही कैसे जा सकता है? और अपने नुकसान का आकलन किए बिना, आइंदा उसी तरह के नुकसान के रास्ते पर चलने से कैसे बचा जा सकता है? लेकिन, स्पष्टरीय सुरक्षा सलाहकार के 'खिड़की का एक कांच तक नहीं टूटा' के दावे इन सवालों के प्रति इस सरकार की दंभपूर्ण अगंभीरता को ही दिखाते हैं।

इस सिलसिले में विपक्ष बेशक खासे प्रभावी तरीके से यह उजागर करने में कामयाब रहा कि राजनीतिक नेतृत्व द्वारा अपनायी गयी सैन्य रणनीति के चलते, इस कार्रवाई के शुरूआती दौर में भारतीय वायु सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा लगता है। याद रहे कि यह सिर्फ विपक्ष का अनुमान नहीं है। सीडीएस समेत विभिन्न शीर्ष सैन्य अधिकारियों द्वारा अलग-अलग मौकों पर की गयी टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि कार्रवाई के शुरूआती दौर में भारत के विमान (एक से अधिक) गिरे थे और यह राजनीतिक नेतृत्व द्वारा तय की गयी सैन्य रणनीति का नतीजा था, जिसके तहत तय किया गया था कि सिर्फ आतंकवाद से जुड़े निश्चित ठिकानों पर प्रहार किया जाएगा और पाकिस्तान के हवाई सुरक्षा तंत्र को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करने और इस रणनीति के खोखलेपन को पहचानने की जगह, मोदी सरकार इस कार्रवाई में हुए नुकसान को छुपाने में ही लगी रही। इसके लिए एक फर्जी बहाना यह बनाया गया कि आपरेशन सिंदूर तो अब भी जारी है, इसलिए उसके नफा-नुकसान का आकलन नहीं किया जा सकता! अगर यह तर्क वाकई गंभीर है तो, इसके सफल होने और अपने सारे लक्ष्य पूरे करने के दावे कैसे किए जा सकते हैं? सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पूछता है भारत कि हमारे कितने विमान गिरे? भारत सबसे बढ़कर इसलिए जानना चाहता है कि काफी नुकसान वाली साबित हुई इसी सैन्य रणनीति को दोबारा नहीं दुहराया जाए। और यही बात अमरीकी मध्यस्थता से हुए शस्त्रविराम के संबंध में सच है। मोदी सरकार, फर्जी राष्ट्रवाद के बवंडर के पीछे इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही है कि वास्तव में सवाल, ऑपरेशन सिंदूर की उपयोगिता तक जाते हैं। अपने सांप्रदायिक रंग में रंगे, राष्ट्रवादी पाखंड के चक्कर में मोदी राज ने, भारत की पड़ोसी नीति और खासतौर पर पाकिस्तान नीति को, तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक्स की मरीचिका में फंसा दिया है। इसने दूसरे तमाम कूटनीतिक रास्तों को बंद कर, भारत को अकेला और कर दिया है। इस छद्म राष्ट्रवाद के ही भ्रमजाल को काटना होगा। आपरेशन सिंदूर की इस बुनियादी विफलता को ही पहचानना होगा।

बदायूं में गंगा किनारे के 11 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, 14 हजार से अधिक लोग फंसे

आर्यावर्त संवाददाता

बदायूं। गंगा में आई बाढ़ का पानी बदायूं जिले के 11 गांवों में घुस गया। इससे 14 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें दातागंज तहसील के सात और सहसवान के चार गांव हैं। इन गांवों में तीन से चार फीट तक पानी भर गया है। घरों में रखी खाद्य सामग्री और कपड़े भीग गए हैं। लोग छतों पर जरूरत की सामग्री जुटाकर रह रहे हैं। मवेशियों को नजदीक के ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया है।

जिले में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को यह खतरे के निशान से सात सेंटीमीटर ऊपर चला गया। कछला में गंगा के खतरे का निशान 162.44 है। बुधवार को जलस्तर 162.51 मीटर पहुंच गया था। दातागंज के गांव कमलईयापुर, कदम नगला, दलपतनगला, रैपुरा, जसवंत नगला, प्रेमी नगला, जटा, ठकुरी नगला में दो से तीन फुट तक बाढ़ का पानी भर गया। इससे 10 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। प्रशासन की ओर से आवाजाही के लिए सभी गांवों में स्टीमर लगाया गया है। गांव के पंचायत घरों और विद्यालयों में शिविर बनाए गए हैं, लेकिन अधिकतर लोग गांव में ही हैं। वह छतों पर रह रहे हैं।

गृहस्थी का सामान भीगा

रैपुरा के गणेश कुमार ने बताया कि घर के अंदर पानी भरने से गेहूं, भूसा, कपड़ा सहित गृहस्थी का सामान भीग गया है। परिवार के सभी लोग छत पर रात गुजार रहे हैं। जसवंत नगला के सुधाकर ने बताया कि पानी भर जाने के कारण मोटरसाइकिल, बिस्तर और गृहस्थी का सामान डूब गया है। परिवार के लोग छत पर गुजारा कर रहे हैं। विधायक राजीव कुमार सिंह ने उसहैत के जाटी और जटा गांव का निरीक्षण कर ग्रामीणों का हाल जाना और उन्हें राहत सामग्री देने की निर्देश एसडीएम को दिए। हालांकि अभी गांव के अंदर पानी नहीं पहुंच पाया है। इस वजह से ग्रामीण अभी रुके हुए हैं।

प्रधान बोले, दो दिन बाद पहुंची सहायता राशि

रैपुरा के प्रधान राकेश कश्यप ने बताया कि गांव में दो दिन से पानी भरा हुआ है। इस वजह से लोग कहीं आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। जानवरों को गांव के बाहर ऊंची जगहों पर बांध दिया गया है। वहीं पर भूसा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दो दिन बाद प्रशासन की ओर से बुधवार को स्टीमर लगाकर ग्रामीणों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। गांव के बलवीर, राजवीर, श्रीकृष्ण, श्रीराम, गजराम, देव सिंह, सीताराम, राजेश, मुकेश ने बताया कि खेतों में हरी सब्जी की फसल की थी। वह पानी में डूब गई है।

सहसवान के चार गांवों में भर गया पानी

सहसवान तहसील क्षेत्र के खागी नगला, वीरसहाय नगला, भमरौलिया, तौफिया नगला गांव में गंगा का पानी तीन से चार फिट तक भर गया है। घरों के नीचे का हिस्सा और सड़क डूब गई है। लोगों ने अभी पानी और बढ़ने की आशंका जताई है। बुधवार को गंगा का पानी गांव तक पहुंच जाने से कुछ लोग सिर पर कपड़े और खाद्य सामग्री की गठरी बनाकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। चार गांवों में 4000 की आबादी प्रभावित है। वहीं, तौफिया नगला गांव में चंद्रपाल, ऋषिपाल, दाताराम, वीरेंद्र, ज्ञान चंद्र, राम सिंह, अतर सिंह के घर पहुंच गया, हालांकि अभी इन लोगों ने मकान खाली नहीं किया।

गांव छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने की अपील

एसडीएम प्रेमपाल सिंह ने भमरौलिया, वीर सहाय नगला, खागी नगला, गिरधारी नगला और तौफिया नगला का भ्रमण किया। उन्होंने आने वाले दिनों में बाढ़ की संभावना को देखते हुए ग्रामीणों से गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। एसडीएम ने बताया कि उन्होंने बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों के रहने के लिए सिठौलिया पुख्ता, कमनपुर बेला, जरीफपुर गढ़िया और औरंगाबाद टप्पा जामनी में आश्रय स्थल बनवाया है। बाढ़ के मद्देनजर क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया है। वह क्षेत्र में कैंप कर हालात पर निगाह रखेंगे, ताकि ग्रामीणों को सहायता प्रदान की जा सके।

ग्रामीण ज्ञानचंद्र ने बताया कि वीरसराय नगला गांव गंगा के निकट है। गंगा का काटन गांव की तरफ तेजी से हो रहा है। घरों में पानी भर गया है। ग्रामीण घर खाली करके पलायन कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए है। गांव से पहले कटान रोकने के लिए प्रबंध किया गया था लेकिन वह नाकाफी रहा। अब गांव तक पानी पहुंच गया है।

ग्रामीण गोपाल ने कहा कि गांव में तेजी से पानी घुस रहा है। जिला प्रशासन ने अब तक कोई इंतजाम नहीं किए हैं। फसल बर्बाद हो चुकी है। कटान होने की वजह से पूरा गांव डूब चुका है। हमारे पास जितनी जमापूंजी थी, वह खर्च हो चुकी है। पिछले चार साल से ग्रामीण परेशान हैं। जिला प्रशासन से जियो ट्यूब लगाने की मांग की गई थी, उसे नहीं लगाया गया है।

अटेना पुल पर पहुंचा गंगा का पानी

दातागंज तहसील क्षेत्र के गंगा पार करीब आठ गांव ऐसे हैं, जहां घरों में पानी घुस गया है। इन गांवों को जाने के लिए उसहैत जटा मार्ग पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिर गया है। जटा को जाने वाली सड़क पूरी तरह से डूब गई है, जिससे गांव समेत गंगा पार के करीब आठ गांव का तहसील से संपर्क टूट गया है। उसहैत में अटेना घाट के पुल पर भी पानी आने लगा है। इससे लोगों की और भी चिंता बढ़ गई है। पुल पर ज्यादा पानी बढ़ा तो फर्रुखाबाद जाने आने का रास्ता भी

नोएडा से साहिबाबाद तक दौड़ेगी मेट्रो, खत्म होगा गाजियाबाद हाईवे का जाम, नमो भारत से भी होगी कनेक्ट

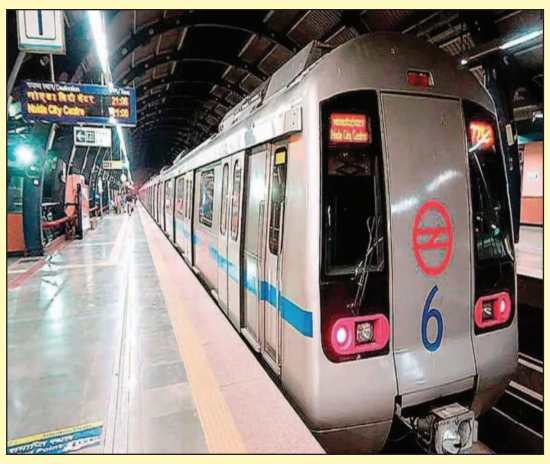

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद तक मेट्रो प्रोजेक्ट की चर्चा फिर से तेज हो गई है। इसे लेकर राज्य सरकार ने विस्तृत जानकारी मांगी है। इस जानकारी में रूट की लागत से लेकर अन्य कई जरूरी जानकारियां मांगी गई है। माना जा रहा है कि इसको लेकर सरकार जल्द ही बैठक करेगी। इस बैठक में प्रोजेक्ट पर निर्णय लिया जा सकता है। गाजियाबाद से रोजाना हजारों की संख्या में लोग नोएडा आते-जाते हैं, जिसके चलते गाजियाबाद से नोएडा आने-जाने वाले मार्ग पर लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ता है।

इस समस्या से निजात पाने के लिए मेट्रो के विकास का विकल्प तलाशा जा रहा है। सरकार ने इस समस्या को खत्म करने का मन बना लिया। लोगों को समस्या से निजात दिलाने के लिए शासन मेट्रो का विकास करने जा रही है। इस परियोजना को लेकर हाल ही में शासन स्तर पर जीडीए अधिकारियों के साथ बैठक हुई।

जल्द शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट

इस बैठक में नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद तक मेट्रो चलाने के प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई। जीडीए अधिकारियों ने शासन को भेजी गई डीपीआर और प्रस्ताव के बारे में पूरी जानकारी दी। साथ ही परियोजना पर आने वाली लागत के बारे में भी बताया गया। अब शासन ने इस परियोजना पर पूरी जानकारी मांगी है, जिसे जल्द ही भेज दिया जाएगा। माना जा रहा है कि परियोजना को लेकर जल्द ही शासन स्तर पर बैठक हो सकती है।

लोगों को मिलेगी राहत

इसके परियोजना से करीब 5 से 6 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा। इससे नोएडा, इंदिरापुरम और वसुंधरा इलाकों में रहने वाले लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा। प्राइवेट वाहनों की संख्या भी सड़कों पर कम होगी। जिससे जाम की समस्या से भी निजात मिलने की उम्मीद है। नमो भारत स्टेशन से जुड़ें होने के नाते इस परियोजना से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ आना-जाना आसान हो जाएगा।

नमो भारत स्टेशन से जुड़ेगा मेट्रो

इस परियोजना में साहिबाबाद मेट्रो को फुटओवर ब्रिज के जरिए नमो भारत स्टेशन के साथ जोड़ा जाएगा। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के अलावा वैभव खंड इंदिरापुरम, डीपीएस इंदिरापुरम, शक्तिखंड इंदिरापुरम और वसुंधरा सेक्टर सात मेट्रो स्टेशन होंगे। आखिरी स्टेशन साहिबाबाद मेट्रो स्टेशन होगा। मेट्रो के इस विस्तार से क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी।

पति गया गंगा स्नान करने, पत्नी पड़ोसी के साथ हो गई फरार, कैश-जेवर और बेटा भी ले गई साथ

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। कानपुर के शिवराजपुर कस्बे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पति गंगा स्नान के लिए घर से बाहर गया था। इसी बीच, उसकी पत्नी मौका देखकर पड़ोसी युवक के साथ फरार हो गई। महिला अपने साथ 5 वर्षीय बेटे, कैश और कीमती जेवरात भी ले गई। पति के घर लौटने पर उसे इस घटना का पता चला, जिसके बाद उसने तुरंत पुलिस से संपर्क किया।

घटना शिवराजपुर के वार्ड नंबर-7 की है। यहां के रहने वाले अजय सिंह ने पुलिस को बताया कि सोमवार सुबह करीब 11 बजे वह गंगा स्नान के लिए निकले थे। दोपहर करीब 2 बजे जब वे घर लौटे तो घर का नजारा देखकर हैरान रह गए। उसकी पत्नी संगीता देवी और बेटा घर पर नहीं थे। अलमारी खुली हुई थी और उसमें रखे नकदी और जेवरात गायब थे। पूरे कमरे का सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था।

पति बोला- पड़ोसी दीपक के साथ पत्नी का है अफेयर

अजय ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले किरायेदारों से पूछताछ करने पर उन्हें जानकारी मिली कि उसकी पत्नी एक बैग और बेटे के साथ 11:30 बजे के आसपास घर से निकली थी और पड़ोसी युवक दीपक उसे साथ ले गया। अजय ने यह भी बताया कि उसे पहले से शक था कि पत्नी और दीपक के बीच कुछ अनैतिक संबंध हैं। वर्ष 2019 में शादी के कुछ समय बाद ही उसने अपनी पत्नी को दीपक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद मकान बदल दिया था, लेकिन दीपक से संपर्क खत्म नहीं हुआ।

अजय ने आगे बताया कि हाल ही में उसे हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण के तहत 15 लाख रुपये का मुआवजा मिला था, जिससे उसने पत्नी के लिए जेवर बनवाए थे और कुछ नकद भी घर पर रखा था। महिला वही सब कुछ साथ लेकर फरार हो गई।

कोचिंग सेंटर का संचालक है दीपक

दीपक पेशे से कोचिंग सेंटर संचालक है, जबकि उसका भाई देवकी कटियार इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता है और बड़ा भाई केसरी दिल्ली में नौकरी करता है। अजय का आरोप है कि दीपक के पूरे परिवार ने इस भगाने की योजना में भूमिका निभाई है। पुलिस ने मामले की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में महिला और दीपक के बीच प्रेम संबंध की पुष्टि हुई है। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है।

विश्व स्तनपान सप्ताह 'एक से सात अगस्त' पर एक संगोष्ठी का आयोजन

आर्यावर्त संवाददाता

बाराबंकी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, की अध्यक्षता में आर०सी०एच० सभागार, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, में विश्व स्तनपान सप्ताह एक से सात अगस्त पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजित संगोष्ठी में शीघ्र एवं शतप्रतिशत स्तनपान (जन्म के एक घण्टे के अन्दर) कराने हेतु जागरूकता एवं स्तनपान से सम्बन्धित लाभों के विषय में विस्तृत चर्चा की गयी। संगोष्ठी में प्रतिभागियों द्वारा अपने-अपने विचार अनुभव साझा करते हुए जनसमुदाय में स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु प्रचार-प्रसार करने का संकल्प लिया गया। साथ ही कामकाजी धात्री महिलाओं के लिए उनके कार्यस्थल पर स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए एक स्तनपान कक्ष स्थापित करने हेतु विशेष प्रयास किये जाने पर विचार विमर्श किया गया। उक्त संगोष्ठी में समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपमुख्य चिकित्साधिकारी सहित कार्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

डीएम ने नगर पालिका बलरामपुर में निर्माणधीन ओवर हेड टैंक का किया निरीक्षण

आर्यावर्त संवाददाता

बलरामपुर। डीएम पवन अग्रवाल द्वारा जल निगम (शहरी) द्वारा नगर पालिका बलरामपुर में निर्माणधीन ओवर हेड टैंक एवं पंप हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम के साथ टेक्निकल टीम मौजूद रही, मास्टर हाउस का कार्य मानकरूप ना पाए जाने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की एवं सहायक अभियंता को फटकार लगाई, उन्होंने तत्काल सभी कमियों को दूर किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को परखा एवं थर्ड पार्टी जांच रिपोर्ट को देखा। समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण किए जाने का निर्देश दिया। इस दौरान अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बलरामपुर व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

झांसी में प्रिंसिपल पर हमला कर भाग रहा था अपराधी 'घोड़ा', मुठभेड़ में लगी गोली, अरेस्ट

आर्यावर्त संवाददाता

झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी में प्रधानाचार्य पर जानलेवा हमला करने वाला शातिर अपराधी रवि उर्फ घोड़ा अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। मंगलवार देर रात शहर की फिजाओं में तब अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी, जब स्वाट और सदर बाजार पुलिस की संयुक्त टीम ने एक हाई प्रोफाइल ऑपरेशन को अंजाम दिया और प्रधानाचार्य पर जानलेवा हमला करने अपराधी रवि उर्फ घोड़ा को पकड़ लिया।

करीब दो हफ्ते पहले एक स्कूल के प्रधानाचार्य को मारने की नीयत से गला दबाकर हमला करने वाले शातिर अपराधी रवि उर्फ घोड़ा की तलाश में पुलिस टीमें लगातार जुटी थीं। इस वारदात के बाद से ही रवि भूमिगत हो गया था और लगातार अपनी लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। इस बार रवि की किस्मत उसे झांसी के ही सिमराहा के जंगलों में ले आई।

खुफिया इनपुट पर पुलिस ने शुरू की तलाश

पुलिस को खुफिया इनपुट मिला कि रवि उर्फ घोड़ा सिमराहा के ही जंगलों में कहीं छिपा हुआ है। इसी इनपुट के आधार पर स्वाट और थाना सदर बाजार पुलिस की टीमें रात के अंधेरे में जंगल की ओर कूच कर गईं और शातिर अपराधी रवि की तलाश शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की, रवि उर्फ घोड़ा ने खुद को फंसता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस भी पूरी तैयारी में थी। जवाबी फायरिंग में रवि के पैर में गोली लगी। इसके बाद जमीन पर गिरते ही रवि की फरारी की कहानी खत्म हो गई। मौके पर पहुंची टीम ने रवि को तुरंत कस्टडी में लिया और उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया। घायल हालत में उसे झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस बीच पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है, जिसमें कई सनसनीखेज मामले जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी

रवि उर्फ घोड़ा झांसी के खिरक पट्टी का रहने वाला है और फिलहाल वो कचहरी चौराहे के पास रह रहा था। प्रधानाचार्य पर हमला उसकी आपराधिक मानसिकता की ताजा कड़ी थी। घटना की जानकारी मिलते ही झांसी के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि रवि अकेले काम कर रहा था या उसके पीछे कोई गैंग भी सक्रिय है।

यूपी-बिहार के 3 आम लोग झटके से बन गए खरबपति, अकाउंट में देखा पैसा, मगर रखने से कर दिया इनकार

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। जरा सोचिए आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर रहे हों और अचानक उसमें इतना पैसा दिख जाए, जिसकी गिनती भी आप न कर पाएं तो? जी हां यूपी के सिद्धार्थनगर से ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां रहने वाले विनय पाण्डेय के बैंक अकाउंट में 37 अंकों की विशाल धनराशि दिखने लगी। यह देख विनय के पसीने छूट गए। उसे समझ ही नहीं आया कि इतना पैसा आखिर आया तो आया कहां से? विनय ने तुरंत बैंक में बैंक में जाकर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया।

विनय पांडेय ने बताया- मैं खेती-बाड़ी का काम करता हूं। मेरा बैंक खाता कोटक महिंद्रा बैंक की सोनीपत शाखा में है। ये मेरा पैसा नहीं है। इसलिए मैं इस पर कोई दावा भी नहीं करना चाहता। मेरे बैंक अकाउंट में जो राशि दिखा रही है वो 10,01,35,60,00,00,00,00,00,01,00,23,56,00,00,09,82,024 रुपये है। इस मामले की जानकारी आयकर विभाग और अन्य संबंधित विभागों को दे दी गई है, जो अब इसकी जांच में जुट गए हैं।

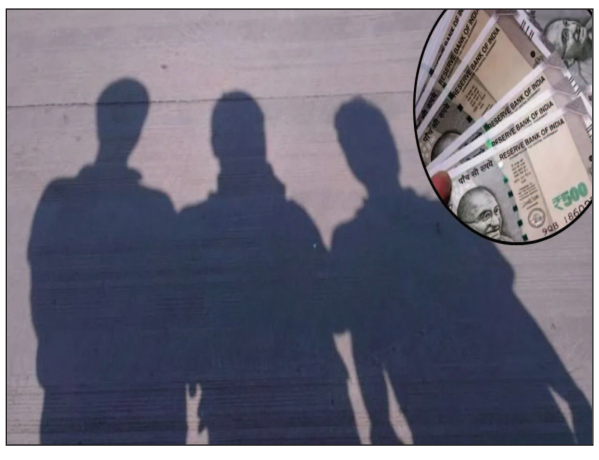

चौंकिए मत। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले ग्रेटर नोएडा के दीपक नाम के शख्स के खाते में भी 37 डिजिट में बैंक बैलेंस दिखा रहा था। 5 अगस्त को दनकौर थाना क्षेत्र के ऊंची दनकौर मोहल्ले में 20 वर्षीय युवक के खाते में अचानक 1 अरब 13 लाख 55 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर हो गए थे। जिससे कुछ देर के लिए वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था। इतनी बड़ी राशि के बारे में पता चलते ही सोशल मीडिया में बवाल मच गया और तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं।

राशि देखकर बैंक अधिकारी भी रह गए सन्न

ये राशि इतनी बड़ी थी कि कई देशों की GDP भी इसके आसपास नहीं पहुंचती। रकम कोटक महिंद्रा बैंक से ट्रांसफर हुई और 36 अंकों की यह राशि देखकर बैंक अधिकारी भी हैरान रह गए। जिसके बाद बैंक ने अकाउंट को तुरंत फ्रीज कर आयकर विभाग को पूरे मामले की जानकारी दी। इस असाधारण ट्रांजैक्शन की भी जांच जारी है। ये पता लगाया जा रहा है कि ये तकनीकी खामी है या फिर साइबर फ्रॉड का हिस्सा।

बिहार के जमुई में मजदूर बना था खरबपति

वहीं, इससे भी पहले बिहार के जमुई से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। यहां रहने वाले एक मजदूर के खाते में 10 खरब, एक करोड़ 35 लाख 6 हजार रुपए आ गए थे। इतने रुपए अकाउंट में दिखने के बाद से मजदूर के होश उड़ गए। मामला अचहरी गांव का है। यहां रहने वाले निवासी टेनी मांझी के बैंक अकाउंट में मंगलवार को अचानक 10 खरब एक करोड़ 35 लाख 6000 रुपए आ गए थे। इतनी बड़ी रकम को देखकर टेनी मांझी के होश उड़ गए। वो पढ़ा लिखा भी नहीं है। इसलिए इतनी रकम तो वो गिन भी नहीं पाया। बाद में बैंक ने उसके खाते को भी फ्रीज कर दिया था।

डीएम की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की एक वृहद समीक्षा बैठक सम्पन्न

आर्यावर्त संवाददाता

बाराबंकी। कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभागार में जिलाधिकारी श्री शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की एक वृहद समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद की बाढ़ से प्रभावित तहसीलों रामनगर, सिरौली गौसपुर एवं रामसनेहीघाट के उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारों से स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा राहत व बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित ग्रामों के नागरिकों एवं उनके पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनके भोजन, आवास, पेयजल एवं चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि आपदा की स्थिति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर प्रभावित तक मदद पहुँचना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व वादों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष बल देते हुए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि तीन वर्ष एवं पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों को चिन्हित कर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार न्यायालयों में पाँच वर्ष से अधिक पुराने कोई भी वाद लंबित न रहें, इसके लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर उसे अमल में लाया जाए। राजस्व संहिता की धारा 24, 34, 80 एवं 116 के अंतर्गत लंबित मामलों का समयबद्ध एवं मेरिट पर आधारित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने तहसील सिरौली गौसपुर को प्रदेश में प्रथम रैंक प्राप्त होने पर एसडीएम एवं उनकी टीम को बधाई दी। साथ ही अन्य तहसीलों को निर्देशित किया कि वे सिरौली गौसपुर की भांति शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के माध्यम से अपनी रैंकिंग सुधारें। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि चिन्हांकन पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी एसडीएम अपनी-अपनी तहसीलों में शासकीय भूमि के बड़े-बड़े टुकड़ों को पूर्व से ही चिन्हित रखें ताकि भविष्य में किसी योजना हेतु भूमि की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) श्री अरुण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक श्री इन्द्रसेन यादव, जॉइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम रामनगर सुश्री गुंजिता अग्रवाल, एसडीएम सदर श्री आनंद तिवारी सहित सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कैंसर और दिल की बीमारियों से बचा सकती है ब्रोकली, पर इसके साइड-इफेक्ट्स भी कम खतरनाक नहीं

फिटनेस इंफ्लुएंसर से लेकर डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट तक, सभी ब्रोकली को सुपरफूड का दर्जा दे चुके हैं। पर इसके सेवन को लेकर कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं क्योंकि इसके कई प्रकार के साइड-इफेक्ट्स भी हो सकते हैं।

भोजन में पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को शामिल करना सेहत को ठीक रखने के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। पौष्टिक आहार से न सिर्फ हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है बल्कि ये आपको बीमारियों से बचाए रखने में भी सहायक है। जब भी बात पोषक तत्वों से भरपूर आहार की होती है तो ब्रोकली फिटनेस के शौकीन लोगों की पसंदीदा चीजों में से एक मानी जाती है।

फिटनेस इंफ्लुएंसर से लेकर डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट तक, सभी ब्रोकली को सुपरफूड का दर्जा दे चुके हैं। असल में, ब्रोकली सिर्फ एक सब्जी भर नहीं है ये पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें मौजूद सल्फोराफेन जैसे तत्व कैंसर से बचाव में मदद करते हैं, वहीं इसका फाइबर और विटामिन्स दिल, पाचन और इम्युनिटी के लिए वरदान हैं।

लो कैलोरी, ज्यादा पोषण और ढेरों फायदों वाली ब्रोकली को भोजन की थाली में शामिल करके आप भी कई लाभ पा सकते हैं। हालांकि इसके सेवन को लेकर कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं क्योंकि इसके कई प्रकार के साइड-इफेक्ट्स भी हो सकते हैं।

पहले ब्रोकली से होने वाले फायदों को जान लीजिए

ब्रोकली पोषक तत्वों का खजाना है, इसका सेवन रोगों से लड़ने की क्षमता और वजन नियंत्रण में सहायक है। कैंसर से बचाव और दिल की सेहत को ठीक रखने में इसके लाभ देखे गए हैं।

कैंसर का कम होता है खतरा

ब्रोकली में मौजूद सल्फोराफेन एक शक्तिशाली यौगिक है, जो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में मदद कर सकता है। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार, सल्फोराफेन शरीर में मौजूद कैंसरकारक एंजाइम को निष्क्रिय करता है और डीएनए को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। ब्रोकली को विशेष रूप से फेफड़े, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और कोलन कैंसर के खतरे को कम करने में प्रभावी पाया गया है।

हार्ट के लिए भी लाभकारी

ब्रोकली हृदय स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसमें मौजूद पोटैशियम, मैग्नीशियम और फाइबर हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। अमेरिका की नेशनल हार्ट, लंग्स एंड ब्लड इंस्टीट्यूट के अनुसार, उच्च फाइबर युक्त आहार जैसे ब्रोकली हृदय रोग का जोखिम 20–25% तक कम कर सकता है। ब्रोकली में सल्फोराफेन और फ्लावोनॉयड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट तत्व धमनियों में सूजन और ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकते हैं, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस (धमनियों में प्लाक जमना) का खतरा घटता है।

ब्रोकली के साइड-इफेक्ट्स भी जानिए

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, ब्रोकली में भरपूर पोषक तत्व होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में इसके सेवन को लेकर सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है। ब्रोकली में मौजूद फाइबर और रैफिनोज पाचन की समस्या पैदा कर सकते हैं।

पोषण विशेषज्ञ, वजन प्रबंधन और हृदय स्वास्थ्य विशेषज्ञ ब्रोकली ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक होती है, लेकिन यह पाचन संबंधी -समस्याओं को जन्म दे सकती है। थायरॉइड के कार्य में बाधा डाल सकती है और कुछ परिस्थितियों में दवाओं के अवशोषण को भी प्रभावित कर सकती है।

क्या कहती हैं आहार विशेषज्ञ?

आहार विशेषज्ञ पायल शर्मा कहती हैं, अधिक मात्रा में सेवन के कारण ब्रोकली में मौजूद फाइबर गैस और सूजन का कारण बन सकती है। कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। इसके अलावा किडनी की समस्या वाले लोगों को इसका सेवन बहुत सावधानी से करना चाहिए।

ब्रोकली एक हाई फाइबर वाली सब्जी है, जिसमें रैफिनोज होता है। यह मानव आंत में ठीक से पचती नहीं है, जिसके कारण गैस बनने, पेट फूलने और ऐंठन जैसी समस्या हो सकती है। थाइरॉइड और कमजोर पाचन वाले भी इसका अधिक सेवन करने से बचें।

चेहरे को चमका सकता है कच्चा दूध, बस इस्तेमाल का सही तरीका जान लें

चेहरे को ग्लोइंग बनाने के लिए बाजार में तमाम स्किन केयर प्रोडक्ट आते हैं। इनके इस्तेमाल से चेहरे को इंस्टेंट ग्लो मिलता है। पर, कई बार ये प्रोडक्ट त्वचा को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आज के समय में अभिनेत्रियों से लेकर आम लोग भी घरेलू नुस्खे आजमाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी के चलते हम आज आपको बताएंगे कच्चे दूध का फायदा।

दरअसल, बाजार में मिलने वाला कच्चा दूध स्किन को काफी लाभ पहुंचाता है। इसका लाभ तब सबसे ज्यादा मिलता है, जब आप इसका इस्तेमाल सही तरह से करेंगी। इसी के चलते आज इस लेख में हम आपको स्किन पर कच्चे दूध के इस्तेमाल का तरीका बताने जा रहे हैं।, ताकि घर बैठे आप पाएं दमकती और निखरती त्वचा.....

चेहरा दमकाने का सामान

2-3 बड़े चम्मच कच्चा दूध
1 चम्मच बेसन

पैक बनाने का तरीका

इसका पैक बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में कच्चा दूध लें। अब इसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स करके पेस्ट तैयार करें। ध्यान रखें कि ये पेस्ट एकदम से पतला न हो जाए। अगर पेस्ट पतला हो गया तो इसे चेहरे पर अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनाएं और थोड़ी देर उसे ऐसे ही रहने दें, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं।

इस्तेमाल का तरीका

अब बारी आती है इस पैक को इस्तेमाल करने की तो उसके लिए सबसे पहले अपना चेहरा और गर्दन अच्छी तरह से धो लें। इसके लिए किसी अच्छे फेसवॉश का इस्तेमाल करें। फेसवॉश इस्तेमाल करवे के बाद आपका चेहरा पूरी तरह से साफ हो जाएगा।

अब एक ब्रश की मदद से मिश्रण को चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं। अब 15-20 मिनट तक सूखने दें। 20 मिनट के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। चेहरा धोने के बाद हल्के हाथों से चेहरे को थपथपाते हुए पोंछ लें। इसके बाद मॉइश्चराइज और टोनर का इस्तेमाल अवश्य करें। इससे आपका चेहरा खिल उठेगा।

कब कर सकते हैं इस्तेमाल

यदि आप इस पैक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो याद रखें कि इसे सिर्फ सप्ताह में 2-3 बार इस पैक का इस्तेमाल करें। इससे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये चेहरे को डैमेंज कर सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा तीन बार इसका इस्तेमाल करें।

बरतें ये सावधानी

इस पैक को इस्तेमाल करने के लिए कुछ सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। दरअसल, ये हर किसी को सूट नहीं करता है। इसलिए यदि पहली बार इस पैक का इस्तेमाल करना है तो पहले पैच टेस्ट करें, ताकी किसी तरह की एलर्जी का खतरा न रहे।

अपनाएं ये रूटीन तो बारिश के मौसम में भी नहीं झड़ेंगे बाल!

बरसात के मौसम में बाल देर से सूखते हैं और अक्सर चिपचिपे, बेजान और रूखे नजर आने लगते हैं। ऐसे में आप अपने बालों की देखभाल कैसे करती हैं?

मानसून में ठंडी बूंदों की फुहारें तपती गर्मी से राहत देकर मन को खुश कर जाती हैं। वहीं बालों की देखभाल मानसून में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस मौसम में हवा में नमी अधिक होती है, जिससे बाल चिपचिपे और कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। ऐसे में मानसून में आपको अपने बालों की विशेष देखभाल करनी होगी।

साफ पानी से धोएं

बारिश का पानी आपको प्राकृतिक और शुद्ध लग सकता है, लेकिन शहरों में यह पानी धूल, गंदगी और प्रदूषित पदार्थों से भरा होता है। जब बाल बारिश के पानी में भीगते हैं तो यह उनकी जड़ों को कमजोर करता है और रूसी, खुजली जैसी समस्याएं बढ़ा देता है। साथ ही जब बरसात में गीले बालों पर ठंडी हवा लगती है तो उनके टूटने और झड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए बारिश में भीगने के बाद बालों को साफ पानी से धोकर जल्दी सूखा लें।

हल्के तेल की मालिश

इस मौसम में बहुत गाढ़े या हैवी तेलों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे बाल चिपचिपे और कमजोर हो सकते हैं। नारियल, बादाम, जैतून या आर्गन जैसे हल्के तेलों से सप्ताह में 1-2 बार हल्का मसाज करें। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। तेल लगाने के बाद एक घंटे तक छोड़ना बेहतर है। रात भर तेल लगाकर सोने से धूल और गंदगी चिपक सकती है, जिससे स्कैल्प में खुजली या संक्रमण हो सकता है।

सल्फेट मुक्त शैंपू

मौसम कोई भी हो, बालों की देखभाल के लिए सौम्य और सल्फेट मुक्त शैंपू का उपयोग जरूरी है, क्योंकि सल्फेट युक्त शैंपू बालों के प्राकृतिक तेल छीन लेता है, जिससे बाल रूखे और कमजोर हो जाते हैं। सल्फेट मुक्त शैंपू स्कैल्प को नुकसान पहुंचाए बिना सफाई करता है। वहीं मानसून में शैंपू के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल जरूर करें। यह बालों की नमी बनाए रखता है।

तौलिया और कंघी

मानसून में बाल भीगना सामान्य है, लेकिन गीले बालों में कंघी करने से वे कमजोर होकर टूटने लगते हैं। आप हमेशा साफ कंघी का ही उपयोग करें और उसे नियमित रूप से धोएं। बाल सुखाने के लिए तौलिए से जोर से रगड़ने के बजाय हल्के हाथों से पोंछें। तौलिया या कंघी किसी के साथ शेयर न करें, ताकि फंगल संक्रमण से बचा जा सके।

कूल मोड पर ड्रायर

स्टाइलिश दिखना जरूरी है, लेकिन बरसात के मौसम में आपको स्ट्रेटनर, ब्लो ड्रायर, हेयर कलर और केमिकल ट्रीटमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि ये बालों को कमजोर और बेजान बना देते हैं। ये उपकरण बालों की प्राकृतिक नमी छीन लेते हैं और बाल रूखे हो जाते हैं। हालांकि अगर ड्रायर का उपयोग जरूरी हो तो 'कूल मोड' पर ही इस्तेमाल करें।

हेयर स्टाइल

खुले बाल आपको पंसद हैं और हर आउटफिट पर अच्छे लगते हैं, लेकिन इस मौसम आपको बाल खूले रखने से बचना चाहिए। आपको एक ऐसा हेयर स्टाइल चुनना चाहिए, जो बालों को सुरक्षित रखे। आप खुले बालों के बजाय चोटी, जूड़ा या बन बना सकती हैं। ये बालों को उलझने और टूटने से बचाते हैं।

सप्ताह में 1 से 2 बार हेयर मास्क लगाएं

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दिल्ली के सीनियर रेजिडेंट, त्वचा विज्ञान विभाग डॉ. अमित कुमार मीणा का मानना है कि बरसात के मौसम में आपके बालों को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। इसलिए सबसे पहले तो आप गीले बालों में बाहर न निकलें। जल्दी है तो बालों को पहले मुलायम तौलिए से हल्के हाथों से पोंछें, फिर हेयर ड्रायर को कम तापमान या 'कूल मोड' पर रखकर बालों को सुखाएं। हीट स्टाइलिंग टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल न करें। बालों की जड़ों को पोषण देने के लिए हाइड्रेशन बनाए रखें, खूब पानी पीएं और संतुलित आहार लें। सप्ताह में 1-2 बार हेयर मास्क या डीप कंडीशनिंग करें। शैंपू के दौरान स्कैल्प की हल्की मालिश करें और टाइट हेयर स्टाइल से बचें। ढीली चोटी या प्राकृतिक स्टाइल को प्राथमिकता दें।

जन धन खातों का री-केवाईसी अब जरूरी, इस दिन तक लगाए जाएंगे कैंप, जानिए ऑनलाइन तरीका

जन धन योजना के दस साल पूरे हो चुके हैं और एसबीआई ने अब जन धन खातों की री-केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए बैंकों ने पंचायत स्तर पर कैंप लगाएं हैं जहां आप ये प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। इसके साथ ही आप ऑनलाइन भी री-केवाईसी की प्रक्रिया घर बैठे कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) को 10 साल पूरे हो गए हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और सरकार ने यह तय किया है कि जन धन खातों का Re-KYC प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। इससे बैंक खातों की जानकारी अपडेट रहेगी और खाताधारकों को बैंकिंग सेवाओं में कोई परेशानी नहीं होगी।

अगर आपका जन धन खाता है, तो अपना री-केवाईसी जरूर पूरा कर लें। इससे आपके बैंकिंग कामकाज में कोई रुकावट नहीं आएगी और आप सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकेंगे। जन धन खातों की री-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कराने के लिए बैंकों द्वारा कैंप भी लगाए जाएंगे। आप ऑनलाइन या पंचायत स्तर पर लग रहे कैंप में जाकर यह प्रक्रिया कर सकते हैं।

कब तक लगेंगे ये री-केवाईसी कैंप?

जन धन खातों के लिए 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक हर पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। बैंक कर्मचारी खुद गांव-गांव जाकर जन धन खाताधारकों की KYC प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं।

इन कैंपों में जन धन खातों का री-केवाईसी के साथ – साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में नामांकन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) में रजिस्ट्रेशन और अटल पेंशन योजना (APY) की जानकारी और पंजीकरण भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही वित्तीय जागरूकता और शिकायत समाधान की भी सुविधा मिल रही है।

री-केवाईसी क्या होता है?

री-केवाईसी में अपनी पहचान और पते की जानकारी को फिर से बैंक में जमा करना होता है। अगर आपके दस्तावेज पुराने हैं या पता बदल गया है, तो आपको ये प्रक्रिया जरूर पूरी करनी चाहिए। री-केवाईसी के लिए जरूरी दस्तावेज में पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड। एड्रेस प्रूफ जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस और एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी।

घर बैठे कैसे करें री-केवाईसी ऑनलाइन तरीका

अगर आप PNB खाताधारक हैं तो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, या एटीएम के जरिए KYC कर सकते हैं। OTP आधारित ई-KYC का विकल्प है। इसके अलावा वीडियो KYC सुविधा भी उपलब्ध है।

अगर आप एसबीआई खाताधारक हैं तो ये तरीका अपनाएं

एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट पर लॉग इन करें।

"My Accounts & Profile" टैब पर क्लिक करें।

"Update KYC" ऑप्शन चुनें।

अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालें।

जिस खाते का KYC अपडेट करना है, उसे चुनें।

नई जानकारी भरें और ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।

OTP डालें और सबमिट करें।

अगर दस्तावेज़ों में कोई बदलाव है, तो शाखा जाकर स्व-घोषणा पत्र (Annexure C) भी भरना होगा।

नहीं बढ़ेगी आपके लोन की ईएमआई , आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव

मुंबई, एजेंसी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को अगस्त की मौद्रिक नीति कमेटी (एमपीसी) के फैसलों का ऐलान किया। एमपीसी की ओर से रेपो रेट को 5.50 प्रतिशत पर स्थिर गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति का रुख न्यूट्रल बरकरार रखा है। केंद्रीय गवर्नर मल्होत्रा ने कहा, आरबीआई ने विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्णायक और दूरदर्शी कदम उठाए हैं। एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया। रेपो दर 5.5 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई। एमपीसी ने न्यूट्रल रुख बनाए रखने का फैसला किया है।

इससे पहले आरबीआई गवर्नर की ओर से जून की मौद्रिक पॉलिसी में रेपो रेट को 0.50 प्रतिशत घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया था। आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। वहीं, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही के लिए 6.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही के लिए 6.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही के लिए 6.3 प्रतिशत निर्धारित किया है।

वहीं, अगले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27) की पहली तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रह सकती है।केंद्रीय बैंक के गवर्नर के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में महंगाई 3.1 प्रतिशत रह सकती है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में महंगाई 2.1 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 3.1 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.4 प्रतिशत सकती है। वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए महंगाई दर अनुमान 4.9 प्रतिशत है।

मल्होत्रा के मुताबिक, एक अगस्त तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 688.19 अरब डॉलर है, जो कि देश के 11 महीने के व्यापारिक आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। आरबीआई फरवरी शुरुआत से अब तक रेपो रेट में एक प्रतिशत की कटौती कर चुका है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में फरवरी में 0.25 प्रतिशत, अप्रैल में 0.25 प्रतिशत और जून में 0.50 प्रतिशत की कटौती की थी।

सरकार किसानों को यूरिया का कम इस्तेमाल करने के लिए कर रही प्रोत्साहित, वैकल्पिक उर्वरकों को अधिसूचित किया

नई दिल्ली, एजेंसी। खेती के लिए संतुलित और उचित उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो-फर्टिलाइजर, डी-ऑइल केक, ऑर्गेनिक कार्बन वर्धक और नैनो-फर्टिलाइजर को अधिसूचित किया है।

इस उद्देश्य देश में खेती में पोषक तत्व प्रबंधन को प्रोत्साहित करना है।

मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य और उसकी उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक खादों और जैव-उर्वरकों के साथ-साथ द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता करना है।

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि मृदा नमूनों को मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए प्रसंस्करण किया जाता है और विभिन्न मापदंडों जैसे पीएच, विद्युत चालकता (ईसी), जैविक कार्बन, उपलब्ध नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्वों (जस्ता, तांबा, लोहा, मैंगनीज और बोरॉन) के लिए उनका विश्लेषण किया जाता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है और मृदा स्वास्थ्य एवं उसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक के बारे में सुझाव देता है।

इस योजना के तहत, किसानों को 25.13 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। देश भर में लगभग 93,781 किसान प्रशिक्षण सत्र, 6.80 लाख प्रदर्शनियां, मृदा स्वास्थ्य कार्ड अनुशंसाओं पर 7,425 किसान मेले/अभियान आयोजित किए गए हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परम्परागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है।

परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, इसमें से, जैविक खाद सहित कृषि/गैर-कृषि जैविक इनपुट के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किसानों को 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट के तहत, किसान उत्पादक संगठन के निर्माण, जैविक इनपुट के लिए किसानों को सहायता आदि के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 46,500 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि योजना के तहत किसानों को ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म जैविक इनपुट के लिए 32,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में 15,000 रुपए शामिल हैं।

भारतीयों के खिलाफ क्यों हिंसक हो रहे हैं आयरलैंड के लोग? अब 6 साल की बच्ची से मारपीट, देश छोड़ने की धमकी

आयरलैंड। आयरलैंड से इन दिनों जो खबरें आ रही हैं वो हर भारतीय को बेचैन कर देने वाली हैं। कभी एक 6 साल की बच्ची पर हमला होता है तो कभी टैक्सी ड्राइवर को निशाना बनाना। बीते कुछ हफ्तों में आयरलैंड में भारतीयों पर लगातार हिंसक हमले हो रहे हैं। अब ये हमले सिर्फ लूटपाट तक नहीं रह गए हैं, बल्कि अब बात साफ-साफ नस्लभेदी हिंसा तक पहुंच गई है।

भारत सरकार के मुताबिक आयरलैंड में करीब 10,000 भारतीय छात्र हैं, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं। उनके मन में अब डर और असुरक्षा का भाव आना स्वाभाविक है। आइए जानते हैं कि आखिर आयरलैंड के लोग भारतीयों को लेकर इतने हिंसक क्यों हो रहे हैं?

वॉटरफोर्ड सिटी में एक छह साल की भारतीय मूल की बच्ची पर कुछ किशोरों ने नस्लीय टिप्पणी की और हमला किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में लड़कों ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया। ये आयरलैंड में भारतीय मूल के किसी बच्चे पर नस्लभेदी हमले की पहली घटना है। इससे पहले डबलिन में लक्ष्मण दास नाम के एक भारतीय शेफ पर हमला हुआ और उनका सामान लूट लिया गया।

इसी डबलिन शहर के एक इलाके बैलीमुन में टैक्सी ड्राइवर लखवीर सिंह के सिर पर बोतल मारी गई और कहा गया कि अपने देश वापस जाओ। इससे पहले एक और मामला टालगट से आया था, जहां एक 40 साल के भारतीय को बुरी तरह पीटा गया और कपड़े तक उतार दिए गए। आरोप लगाया गया कि उन्होंने बच्चों के आसपास कुछ गलत किया, लेकिन आयरलैंड की पुलिस गार्दिया ने इस बात से इनकार किया। इन सब घटनाओं ने वहां रहने वाले 80,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

भारतीय क्यों हैं निशाने पर?

आयरलैंड में भारतीयों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जनगणना के आँकड़े बताते हैं कि पिछले एक दशक में आयरलैंड में भारतीय मूल के नागरिकों की संख्या में लगभग 300% की बढोतरी हुई है। खासकर हेल्थकेयर, IT और शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयों की मजबूत मौजूदगी है। जिससे लोगों में असंतोष बढ़ा है। कुछ लोगों को लगता है कि भारतीय उनकी नौकरियां छीन रहे हैं। कई बार सोशल मीडिया या लोकल राजनीति में ऐसा नैरेटिव बन जाता है कि प्रवासी लोग सिस्टम पर बोझ हैं। इससे आम लोग भी प्रभावित होते हैं।

भारत सरकार और दूतावास की प्रतिक्रिया

भारतीय दूतावास ने आयरलैंड में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि सुनसान जगहों पर न जाएं। सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या दूतावास को देने की बात कही गई है। लोगों से इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर सेव रखने की भी सलाह दी गई है। साथ ही, दूतावास आयरिश प्रशासन से इन मामलों की जांच और कार्रवाई की मांग कर रहा है।

आयरलैंड में भारतीयों की संख्या कैसे बढ़ी?

The Hindu की एक खबर के मुताबिक ब्रेक्जिट Brexit ने इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई। ब्रेक्जिट के बाद आयरलैंड यूरोपीय संघ (EU) में लगभग एकमात्र अंग्रेजी बोलने वाला देश रह गया, जिससे उसे दुनियाभर के प्रवासियों को आकर्षित करने में बढ़त मिली। बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस, रोजगार के बढ़ते अवसर और अंग्रेजी-भाषी देश होने के कारण ज्यादा से ज्यादालोग आयरलैंड को पसंद करने लगे। और समय के साथ भारतीय वहां की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रवासी आबादी बन गए हैं।

भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी से परेशान हैं ट्रंप, इसलिए लगा रहे टैरिफ पर टैरिफ

वॉशिंगटन, एजेंसी। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते तल्ख होते दिख रहे हैं। कई दौर की बातचीत के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एकतरफा फैसला लेते हुए आखिरकार भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया। हालांकि उन्होंने कई और देशों पर भी ऐसे कड़े फैसले लेने की बात कही है। कुछ समय तक भारत और पीएम नरेंद्र मोदी का गुणगान करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप आखिर इतने सख्त कैसे हो गए कि उन्होंने 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया। जबकि अन्य देशों के साथ नरमी बरती गई है। आखिर इन सबके पीछे वजह क्या है, अमेरिका चाहता क्या है?

इसका सीधा जवाब यही है, अमेरिका चाहता है कि भारत उसका पिछलग्गू बने। जबकि भारत की ओर से ऐसा कोई संकेत तक नहीं दिया गया है। भारत किसी भी मसले पर स्वतंत्र रूप से फैसला लेने के अपने रवैये पर टिका हुआ है, जो अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। इसीलिए भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका अब टैरिफ को अपना बड़ा हथियार बना रहा है।

भारत जिस तरह से रूस और यूक्रेन के मसले पर तटस्थ बना रहा यह अमेरिका को पसंद नहीं आया। वह चाहता है कि भारत वाशिंगटन के साथ कदमताल करता दिखे। यूक्रेन के साथ लड़ाई के बीच भी भारत लगातार रूस से तेल की खरीद करता रहा। खास बात यह है कि तेल खरीद की यह दर लगातार बढ़ी ही है, कम नहीं हुई। अमेरिका का मानना है कि भारत की ओर से रूस से तेल खरीदने की वजह से मास्को को राहत मिली हुई है और वह यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने को राजी नहीं हो रहा। हालांकि चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है और वह इस मामले में पहले पायदान पर है। भारत लगातार रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने से पहले भारत रोजाना करीब 68,000 बैरल तेल खरीदा करता था, जो मई 2023 में बढ़कर 21.5 लाख बैरल हो गया और आज की उसकी तेल जरूरतों का करीब 40 प्रतिशत हो गया, और इसे खरीददारी को राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध करने वाले रूस की आर्थिक रूप से मदद करने के रूप में देखते हैं।

BRICS की सक्रियता को लेकर अमेरिका नाराज

पिछले दिनों राष्ट्रपति ट्रंप की तरह व्हाइट हाउस के प्रवक्ता स्टीफन मिलर ने भारत की ओर से रूसी तेल की लगातार खरीद को "अस्वीकार्य" करार दिया। हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि भारत रूस के साथ अपने दीर्घकालिक घनिष्ठ संबंधों को किस हद तक कम करने के लिए तैयार होगा। भारत के सामने अमेरिका से अपने संबंधों में मजबूती लाने और बढ़ते चीनी खतरे को देखते हुए पश्चिमी सैन्य गठबंधन के करीब जाने का दबाव बढ़ रहा है, नई दिल्ली को इस पर अपना फैसला लेना है। रूस से तेल खरीदना ही नहीं बल्कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपने पारंपरिक दोस्त रूस और ब्रिक्स देशों का साथ छोड़कर पश्चिमी गुट में शामिल हो जाए। वह लंबे समय से इस कोशिश में भारत को अपने साथ जोड़ा जाए। ब्रिक्स में भारत के अलावा ब्राजील, चीन और रूस जैसे अहम देश शामिल हैं और संगठन अमेरिका दुनिया में पश्चिमी असर को कम करना चाहते हैं।

साथ ही, अमेरिका चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल करना चाहता है। उसकी योजना भारत का इस्तेमाल उसी तरह से करने की है जैसा उसने रूस के खिलाफ यूक्रेन का किया। अमेरिका भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी से परेशान है, और ट्रंप की असली परेशानी इसी बात से है। वह भारत को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी का मतलब यह होता है कि कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए आगे बढ़ने और अन्य देशों पर बहुत अधिक निर्भरता की जगह अपनी स्वछंद विदेश नीति अपनाना होता है।

अफगानिस्तान कैसे बना महिलाओं के लिए जहन्नुम, तालिबान ने इसे बनाया सबसे बड़ा हथियार

काबुल। अफगानिस्तान के तालिबान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र मानवाधिकार जांचकर्ता रिचर्ड बेनेट ने चिंता व्यक्त की। बेनेट ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को सौंपी एक रिपोर्ट में बताया कि तालिबान शासको ने महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार करने के लिए कानूनी और न्यायिक व्यवस्था को हथियारबंद कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर है।

रिचर्ड बेनेट ने बताया कि 2021 में सत्ता हथियाने के बाद, तालिबान ने 2004 के संविधान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि इन कानूनों में बलात्कार, बाल विवाह और जबरन विवाह सहित महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे अपराध शामिल थे।

बेनेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तालिबान ने पिछली अमेरिका समर्थित सरकार के सभी न्यायाधीशों को बर्खास्त कर दिया, जिनमें लगभग 270 महिलाएं भी शामिल थीं। इन न्यायधीशों की जगह ऐसे लोगों को न्यायाधीश नियुक्त किया जो कट्टर इस्लामी विचारों को मानते थे। उन्हें कानून या न्याय की कोई समझ नहीं है। वह तालिबान द्वारा जारी किए गए आदेशों के आधार पर फैसले सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा तालिबान ने कानून प्रवर्तन और जांच एजेंसियों पर पूरा कंट्रोल कर लिया है और पिछली सरकार के लिए काम करने वाले सभी अफगान व्यक्तियों को उनके पद से हटा दिया है।

बेनेट ने कहा कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तब से महिलाओं और लड़कियों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है और इसकी व्यापक रूप से भी काफी निंदा की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि तालिबान नेताओं ने छठी कक्षा के बाद महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर रोक लगा दी है और रोजगार पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं महिलाओं को पार्क, जिम और हेयरड्रेसर सहित कई सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस नए कानून महिलाओं की आवाज और घर के बाहर बिना चेहरा ढके जाने पर भी प्रतिबंध है। बेनेट ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों पर अपने प्रतिबंधों के कारण तालिबान पश्चिम से अलग-थलग है और उसे केवल रूस ने ही मान्यता दी है।

बेनेट ने बताया कि तालिबान अपने दृष्टिकोण का बचाव करने के लिए यह दावा करते हैं कि वे इस्लामी शरिया कानून लागू कर रहे हैं। लेकिन इस्लामी विद्वानों और अन्य लोगों का कहना है कि उनकी कानून अन्य मुस्लिम-बहुल देशों में अलग है और इस्लामी शिक्षाओं का पालन नहीं करती। उनका कहना है कि महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा प्राथमिकता है।

महिलाओं के पास नहीं है कोई अधिकार

बेनेट ने बताया कि तालिबान में महिलाओं के पास कोई भी अधिकार नहीं हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि तालिबान में कोई महिला न्यायाधीश या वकील नहीं हैं। पुलिस और अन्य संस्थानों में भी कोई महिला अधिकारी नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की व्यापक रूप से कोई रिपोर्टिंग ही नहीं हो पाती है। उन्होंने कहा कि तालिबान की यह अनिवार्यता है कि अगर कोई महिला शिकायत दर्ज करवाती है तो उसके साथ एक पुरुष होना अनिवार्य है, ये कई मायनों में बाधाएं पैदा करती हैं।

अदालत महिलाओं की शिकायत कर देती है रद्द

बेनेट ने बताया कि तालिबान की अदालतें अक्सर महिलाओं द्वारा की गई शिकायतों को खारिज कर देती है और तलाक, बच्चों की कस्टडी और लिंग आधारित हिंसा से संबंधित मामलों को स्वीकार करने में आनाकानी करती हैं। बेनेट ने कहा कि इन बाधाओं का सामना करते हुए, महिलाएं औपचारिक जिरगा और शूरा जैसी पारंपरिक तरीकों की ओर जा रही है, इसमें गांव या समुदायों में बुजुर्गों की परिषदें होती हैं, जो आपसी झगड़ों को सुलझाती हैं और कुछ महिलाएं धार्मिक नेता या परिवार के बुजुर्गों से मदद मांगती है। बेनेट का कहना है लेकिन ये सारा सिस्टम पुरुष-प्रधान हैं, तो स्वाभाविक है कि महिलाओं या लड़कियों के अधिकारों का हनन होगा और इंसाफ मिलने के चांस बहुत कम हो जाते है।

आईसीजे में लाने का किया अनुरोध

बेनेट ने अपील करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच न्याय दिलाने की बड़ी उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने तालिबान के दो वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ महिलाओं के साथ लैंगिंग आधार पर उत्पीड़न करने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया।

सीपीएम नेता की हत्या मामला: हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बावजूद निचली अदालत से मिली बेल; जांच के आदेश

अगरतला। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने हत्या के छह आरोपियों को बेलोनिया की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा दी गई जमानत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में रजिस्ट्रार (न्यायिक) को जांच के आदेश दिए हैं और आरोपियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनकी जमानत रद्द क्यों न की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति बिश्वजीत पालत ने बुधवार को दिया।

दरअसल, छह आरोपियों ने पहले निचली अदालत में जमानत की

याचिका लगाई थी, जिसे अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने भी सबूतों को मजबूत मानते हुए मार्च में उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बावजूद 25 जुलाई को निचली अदालत ने उन्हीं आरोपियों को फिर से जमानत दे दी, जिससे न्यायिक प्रणाली की गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं।

यह पूरा मामला सीपीआई (एम) के उम्मीदवार बादल शील की हत्या से जुड़ा है। पिछले साल 12 जुलाई को दक्षिण त्रिपुरा जिले के चोत्ताखोला क्षेत्र में बादल शील पर कुछ लोगों ने बेरहमी से हमला किया था। उन्हें गंभीर हालत में अगरतला के जीबीपी अस्पताल लाया गया, जहां अगले दिन उनकी मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सात लोगों को गिरफ्तार किया और जांच के बाद उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

फिर जमानत मिलने पर हाईकोर्ट नाराज

जमानत याचिका खारिज होने के बावजूद जब निचली अदालत ने फिर से बेल दे दी तो यह मुद्दा हाईकोर्ट के समक्ष लाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता पुरषोत्तम रॉय बर्मन ने अदालत में तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट का यह फैसला हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है और यह न्यायिक अनुशासन के खिलाफ है। इस पर न्यायमूर्ति पालत ने गंभीर रुख अपनाते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच आवश्यक है।

जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी

अब हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, रजिस्ट्रार (न्यायिक) यह जांच करेंगे कि किन परिस्थितियों में निचली अदालत ने हाईकोर्ट के पूर्व आदेश को नजरअंदाज करते हुए आरोपियों को जमानत दी। साथ ही छहों आरोपियों से जवाब मांगा गया है कि क्यों न उनकी जमानत तत्काल प्रभाव से रद्द की जाए। इस मामले को लेकर त्रिपुरा की न्याय व्यवस्था में हलचल मची हुई है और आने वाले दिनों में हाईकोर्ट की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

जम्मू कश्मीर में लोग नहीं पढ़ पाएंगे ये 25 किताबें, सरकार ने क्यों किया बैन?

जम्मू, एजेंसी। जम्मू कश्मीर की सरकार ने 25 किताबों को बैन कर दिया है। इसमें बुकर विजेता अरुंधति रॉय और संवैधानिक विशेषज्ञ एजी नूरानी की किताबें भी हैं। इन पुस्तकों को जब्त करने का भी आदेश दिया गया है। गृह विभाग की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है, सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ साहित्य जम्मू-कश्मीर में झूठे विमर्शों और अलगाववाद का प्रचार करते हैं।

बयान में कहा गया है कि जांच और विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर आधारित उपलब्ध साक्ष्य स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि हिंसा और आतंकवाद में युवाओं की भागीदारी के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक झूठे विमर्शों और अलगाववादी साहित्य का व्यवस्थित प्रसार रहा है, जो अक्सर ऐतिहासिक या राजनीतिक टिप्पणी के रूप में आंतरिक रूप से प्रसारित होता रहता है। आदेश में आगे कहा गया है ऐसा साहित्य भारत के खिलाफ 'युवाओं को गुमराह करने, आतंकवाद का महिमामंडन करने और हिंसा भड़काने' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जिन लेखकों की किताबों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें विक्टोरिया स्कोफील्ड, सुमंत्रा बोस और क्रिस्टोफर स्नेडेन भी शामिल हैं। एजी नूरानी ने कश्मीर और उसके

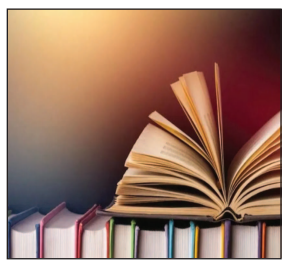

भारत में विलय के बाद उसकी संवैधानिक व्यवस्था पर व्यापक रूप से लिखा है। उनकी पुस्तक द कश्मीर डिस्प्यूट 1947-2012 पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसे जब्त कर लिया गया है।

ब्रिटिश लेखिका और इतिहासकार विक्टोरिया स्कोफील्ड की पुस्तक कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट – इंडिया, पाकिस्तान एंड द अनएंडिंग वॉर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुमंत्र बोस द्वारा लिखित दो पुस्तकें कंटेस्टेड लैंड्स और कश्मीर एट द क्रॉसरोड्स प्रतिबंधित और जब्त प्रकाशनों में शामिल हैं।

पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित अरुंधति रॉय की आज़ादी भी अब जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधित पुस्तकों में शामिल है। पिओटर बाल्सेरोविज और एग्निएस्का कुस्ज़ेवस्का द्वारा लिखित लॉ एंड कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन प्रतिबंधित सूची में शामिल एक अन्य किताब है।

उपराष्ट्रपति पद के उपचुनाव की अधिसूचना हुई जारी, नोमिनेशन प्रक्रिया शुरू, 9 सितंबर को होगी वोटिंग

नई दिल्ली, एजेंसी। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग पहले ही इस बात का ऐलान कर चुका है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होंगे, साथ ही नतीजे भी इसी दिन सामने आ जाएंगे। हालांकि, अब अधिसूचना जारी करने के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

अधिसूचना के अनुसार, चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। साथ ही नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त है।

उपराष्ट्रपति का पद 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे देने के बाद खाली हो गया था। जगदीप धनखड़े ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा। हालांकि, धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 में समाप्त होना था। धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद अब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए दल तैयारियों में जुट गए हैं।

लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति के चुनाव में आम लोग वोट नहीं करते हैं। यह चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव से अलग होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट करते हैं। साथ ही सभी सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (proportional representation system) के तहत वोट करते हैं।

चुनाव में उम्मीदवार बनने की क्या हैं शर्तें

कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति तब तक नहीं चुना जा सकता जब तक वो भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य न हो। साथ ही व्यक्ति किसी लाभकारी पद (office of profit) पर न हो—चाहे वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय/सार्वजनिक प्राधिकरण हो।

उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। साथ ही उच्च सदन के मनोनीत सदस्य भी वोटिंग करने के पात्र होते हैं। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल पांच साल का होता है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद, वो तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले।

सोनाक्षी सिन्हा की पहली तेलुगु फिल्म जटाधारा का पोस्टर जारी, 8 अगस्त को रिलीज होगा टीजर

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पिछली बार फिल्म निकिता रॉय में नजर आई थीं, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया। हालांकि, यह बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। आने वाले समय में सोनाक्षी एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगी। इन्हीं में एक है जटाधारा, जिसके लिए सोनाक्षी को साउथ के स्टार सुधीर बाबू का साथ मिला है। अब जटाधारा का पहला पोस्टर सामने आ गया है, जिसमें सोनाक्षी और सुधीर की झलक दिख रही है।

पोस्टर में सोनाक्षी का रौद्र रूप दिख रहा है, वहीं सुधीर का भी धाकड़ अवतार दिख रहा है। खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिए सोनाक्षी तेलुगु सिनेमा में कदम रखने वाली हैं। जटाधारा की टीजर 8 अगस्त, 2025 को रिलीज होगा। फिल्म में सोनाक्षी को एक सशक्त और अलग तरह की भूमिका के लिए चुना गया है। जटाधारा एक्शन और सस्पेंस से भरपूर एक मनोरंजक फिल्म है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

जटाधारा, ज़ी स्टूडियोज़ और प्रेरणा अरोड़ा के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग का प्रतीक है, जिन्होंने पहले टॉयलेटः एक प्रेम कथा और पैडमैन जैसी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फ़िल्मों का निर्माण किया है। फ़िल्मि की निर्माण टीम में उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा शामिल हैं, जबकि सह-निर्माता अक्षय केजरीवाल और कुसुम अरोड़ा हैं। रचनात्मक निर्माता दिव्या विजय हैं।

अपने आकर्षक पोस्टर और आशाजनक कहानी के साथ, जटाधारा प्रशंसकों के बीच काफ़ी चर्चा बटोर रही है। भारतीय पौराणिक कथाओं, ज़बरदस्त एक्शन और विश्वस्तरीय वीएफएक्स के मिश्रण से फ़िल्मि को एक सिनेमाई तमाशा बनाने की उम्मीद है। जैसे-जैसे यह मिथक जागृत होता है, दर्शक बड़े पर्दे पर एक मनोरंजक अनुभव की उम्मीद कर सकते हैं। इसका टीज़र 8 अगस्त, 2025 को रिलीज़ होगा, जो प्रशंसकों को जटाधारा की दुनिया की एक झलक दिखाएगा।

इस वजह से रुबीना दिलैक ने स्वीकारा पति पत्नी और पंगा का ऑफर

लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री रुबीना दिलैक और उनके पति अभिनव शुक्ला पॉपुलर शो पति-पत्नी और पंगा में नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने के साथ बातचीत में बताया कि उन्होंने मां बनने के बाद शो का ऑफर क्यों स्वीकार किया।

अभिनेत्री ने बताया, इस शो की कहानी उनकी जिंदगी के नए दौर से मेल खाती है। साथ ही इस शो के जरिए उन्हें अपने पति अभिनव के साथ स्क्रीन पर नया अनुभव करने का मौका मिला। मां बनने के बाद मैं अपने पति के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी। कुछ मस्ती भी करनी थी, इसलिए मैंने यह शो किया।

जब अभिनेत्री से पूछा गया, क्या रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होते हैं?

छोटी बहू फेम अभिनेत्री ने बताया, रियलिटी शो स्क्रिप्टेड नहीं होते, लेकिन उन्हें थोड़ा निर्देशित किया जाता है। अगर कोई चीज अच्छी चल रही हो, तो शो के निर्माता उसे और हाइलाइट करते हैं। यह स्क्रिप्टेड नहीं, बल्कि गाइडेड होता है।

वहीं, अभिनेता अभिनव शुक्ला ने रियलिटी शो में स्क्रीन टाइम और रिश्तों की लंबी उम्र के बारे में भी बात की। उनके मुताबिक, रिश्ते में जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम होता है, रिश्ता उतना ही कम समय तक चल सकता है।

रुबीना ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा, अभिनव सही कह रहे हैं। जितना ज्यादा हम एक-दूसरे की बातों और सोच को स्वीकार करेंगे, रिश्ता उतना ही बेहतर होगा। एक अच्छा रिश्ता तब बनता है, जब हम एक-दूसरे को वैसे ही अपनाएं, जैसे हम हैं। जब हम ये समझते हैं कि हम अलग हैं और फिर भी एक-दूसरे की इज्जत करते हैं, तो रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ती है।

अभिनव शुक्ला ने बताया कि जब किसी बात पर बहस या मतभेद होता है, तो वह उसे संभालने का एक शांत तरीका अपनाते हैं।

अभिनव ने कहा, जब हम दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है, तो मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूं, या फिर रुबीना को स्पेस देता हूं, थोड़ी देर बाद शांत होकर दोबारा उस बात पर चर्चा करता हूं, ताकि समस्या आसानी से सुलझ जाए। कुछ परेशानियां, कुछ घंटों में सुलझ जाती हैं, तो कुछ में ज्यादा समय लग जाते हैं।

अभिनव ने मजाकिया अंदाज में कहा, हमारे रिश्ते में तो मैं बस यही कहता हूं, जो तुम कहो। और, अब ये लाइन काफी फेमस हो गई है।

शो की शुरुआत 2 अगस्त से हो चुकी है और इसे कलर्स टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है। शो को अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे और कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी होस्ट कर रहे हैं।

120 बहादुर का टीजर जारी, मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका में खूब जंचे फरहान अख्तर

इंडो-चाइना वॉर पर आधारित रजनीश घई की निर्देशित 120 बहादुर सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार है। मेकर्स ने 120 बहादुर का टीजर जारी किया है, जो काफी दमदार है। फिल्म में बॉलीवुड एक्टर-फिल्म मेकर फरहान अख्तर अहम भूमिका निभा रहे है। यह फिल्म नवंबर 2025 में रिलीज होगी।

2021 में आई फिल्म तूफान के बाद फरहान अख्तर फिल्म 120 बहादुर के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। दमदार पोस्टरों के बाद मेकर्स ने मंगलवार को एक 120 बहादुर का टीजर जारी किया, जिसमें फरहान भारतीय सेना के वर्दी पहने नजर आ रहे हैं। फिल्म में वह मेजर शैतान सिंह भाटी (पीवीसी) की भूमिका निभा रहे हैं। रेजांग ला युद्ध पर आधारित, 120 बहादुर के टीजर ने साहस और बलिदान पर आधारित सिनेमाई युद्ध की एक झलक पेश की है।

फरहान अख्तर ने इंस्टाग्राम पर 120 बहादुर का टीजर साझा किया है। उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ये वर्दी सिर्फ हिम्मत नहीं, बलिदान भी मांगती है। बर्फ में गढ़ी और बलिदान से सजी एक अविश्वसनीय सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म। 120 बहादुर का टीजर अभी रिलीज हुआ है। 21 नवंबर, 2025 को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

टीजर की शुरुआत एक सवाल से होता है, जिसमें पूछा जाता है, रेजांग ला में 18 नवंबर को आखिर क्या हुआ था। इसके बाद 1962 में हुई भारत-चीन के युद्ध की झलक दिखाई जाती है। टीजर में दिखाया गया कि कैसे -24 डिग्री के तापमान में भारतीय सेना चीन के होने वाले हमले की तैयारी में जुटे हुए थे। इस दौरान मेजर शैतान सिंह भाटी के साहस का परिचय दिखाया जाता है कि कैसे -24 डिग्री तापमान में वह दुश्मनों पर नजर जमाए हुए थे।

टीजर में यह भी दिखाया गया कि कैसे उन्होंने 120 जवानों का नेतृत्व करते हुए लद्दाख की रखा की। मेजर शैतान सिंह भाटी (पीवीसी) के रूप में फरहान टीजर में कहते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। बता दें, भारतीय सेना की 13 कुमाऊं बटालियन के मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में रेजांग ला की लड़ाई भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लड़ी गई थी।

120 बहादुर को रजनीश घई ने निर्देशित किया है। जबकि इसे रितेश सिधवानी-फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियो) द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में फरहान अख्तर के साथ राशि खन्ना अहम भूमिका में नजर आएंगी। यह फिल्म लद्दाख, राजस्थान और मुंबई में फिल्माई गई है। फिलहाल यह फिल्म 120 बहादुर 21 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com